



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2019/ श्रावण 10, 1941

No. 228]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/ SHRAVANA 10, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय : ब्राजील, चीन और जर्मनी से नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. **फा. सं. 6/23/2018.—डीजीटीआर.**—मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड (जिसे यहां आगे याचिकाकर्ता अथवा आवेदक भी कहा गया है) ने "तीन तत्वों अर्थात् मॉलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनेडियम वाले नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील जिसमें से टंगस्टन और मॉलीब्डेनम का संयोजन 4 प्रतिशत – 11.5 प्रतिशत और वेनेडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत, कार्बन 0.7 प्रतिशत – 1.3 प्रतिशत के बीच और क्रोमियम 3.5 प्रतिशत – 4.6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए" (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान अथवा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) भी कहा गया है), ब्राजील, चीन और जर्मनी (जिन्हें यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. जबकि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभार निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए और पाटनरोधी शुल्क की राशि जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 14 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 6/23/2018-डीजीटीआर जारी की।

क. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी ने संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के तहत घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त किया जिसमें ब्राजील, चीन और जर्मनी से "तीन तत्वों अर्थात् मॉलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियम वाले नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील जिसमें से टंगस्टन और मॉलीब्डेनम का संयोजन 4 प्रतिशत – 11.5 प्रतिशत और वेनेडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत, कार्बन 0.7 प्रतिशत – 1.3 प्रतिशत के बीच और क्रोमियम 3.5 प्रतिशत – 4.6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए" (जिन्हें यहां आगे संबद्ध सामान अथवा विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है।
 - प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में चीन, ब्राजील और जर्मनी के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 14.08.2018 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - प्राधिकारी ने भारत में उपर्युक्त दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
 - प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को संगत सूचना देने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं और लिखित में अपने ज्ञात विचार देने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया:
 - क. मैसर्स एचईवाईई स्पेशल स्टील कं. लि., चीन
 - ख. मैसर्स जियांगसु टियानगोंग टूल्स कं. लि.
 - ग. मैसर्स हुआंगशी जिरुई इंडस्ट्री कं. लि.
 - घ. मैसर्स विल्लेयर्स मेटल्स एसए
 - ङ. मैसर्स डच एडलस्टेहलवर्क सर्विसेज जीएमबीएच
 - प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए 22 अक्तूबर, 2018 तक का भी समय बढ़ाने की अनुमति दी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
 - क. एचईवाईई स्पेशल स्टील कं. लि., चीन
 - ख. टियानगोंग डेवलेपमेंट हांगकांग कंपनी लिमिटेड
 - ग. जियांगसु टियानगोंग टूल्स कंपनी लिमिटेड
 - प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें:

- क. एडिसन एंड कं. लि.
 ख. एसोसिएट टूल मैनुफैक्चरर
 ग. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
 घ. चमन स्टील कारपोरेशन
 ङ. चाँगुले मैट्रिक्स हॉब्स लि.
 च. कमिंस इंडिया लिमिटेड
 छ. ड्रिलाबाइट्स इंटरनेशनल प्रा. लि.
 ज. एमके टूल्स
 झ. एसगी टूल्स प्राइवेट लि.
 ञ. एसके स्टील्स
 ट. फैरोकेयर इंटरनेशनल
 ठ. फॉर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड
 ड. फ्यूचर्स्टिक अलॉयज एंड मेटल्स प्रा. लि.
 ढ. गोयल स्टील कंपनी
 ण. गन एंड शेल फैक्ट्री
 त. इमी अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
 थ. इंडो स्कोटल ऑटो पार्ट्स प्रा. लि.
 द. इजर
 ध. जे. के. फाइल्स एंड टूल्स
 न. जलधारा टूल्स एंड अलॉय स्टील्स
 प. कादिमी टूल मैनु. कं. प्रा. लि.
 फ. केस्को स्पेशल टूल्स लि.
 ब. मैसर्स डेलफी-टीवीएस डीजल सिस्टम्स लि.
 भ. मैसर्स. लुकास-टीवीएस लि.
 म. मैनी प्रीसिसन प्रोडक्ट्स (पी) लि.
 य. मानेक टूल्स
 कक. मिरांडा टूल्स
 खख. मित्सुबिशी हैवी इंस इंड. प्री. टिक. लि.
 गग. मदरसन एडवांस्ड टूलिंग सॉल. लि.
 घघ. ओम स्टील इंटरप्राइजेज
 ङङ. आर के इंटरप्राइजेज

- चच. रिफिल फैक्ट्री
- छछ. रोहित इंडस्ट्रीज ग्रुप पी. लि.
- जज. एस. आर. पी. टूल्स लि.
- झझ. सीतवीका ट्रेडिंग कंपनी
- ञञ. साक्षी स्टील – एन - अलॉयज
- टट. स्टीलमेन इंटरप्राइजेज
- ठठ. टूलमेन इंडस्ट्रीज
- डड. ट्राइडेंट टूल्स प्रा. लि.
- ढढ. यूनाइटेड सेल्स इंटरप्राइजेज
- णण. उषा इंटरनेशनल लि.
- तत. जेनिथ बिरला (इंडिया) लि.
- viii. उपर्युक्त मामले में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने अपने अनुरोध/अभ्यावेदन दायर किए हैं:
- क. टीजीके स्पेशल स्टील प्रा. लि.
- ख. मिरांडा टूल्स प्रा. लि.
- ग. जे के फाइल्स (इंडिया) लि.
- घ. एडिसन एंड कं. लि.
- ङ. बिरला प्रीसिसन टेक्नोलॉजीस लि.
- च. कटिंग टूल्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन
- ix. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- x. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत निकालने के लिए अनुबंध-III में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के आधार पर यथा संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xi. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े अर्थात् अप्रैल, 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017 तथा जांच की अवधि के आंकड़े शामिल होंगे।
- xii. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक और सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- xiii. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiv. भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों के मूल्य एवं मात्रा के निर्धारण के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से लेन-देन वार आंकड़े मांगे गए थे।

- xv. मैसर्स टीजीके स्पेशल स्टील प्रा. लि. और जेके फाइल्स (इंडिया) लि. द्वारा दायर आंकड़ों का सत्यापन भी किया गया था।
- xvi. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार, मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 07.02.2019 को एक मौखिक सुनवाई की। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दायर करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों पर अपने प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। उसमें किए गए अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है और उपयुक्त रूप से उनका समाधान किया गया है।
- xvii. जिन निर्यातकों, उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना दी है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है और प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को रिकार्ड किया है।
- xviii. प्राधिकारी ने 16 जुलाई, 2019 को नियम 16 के तहत प्रकटन विवरण जारी किया और 23 जुलाई, 2019 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया। दायर टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। पूर्व में जिन संगत अनुरोधों को हल नहीं किया गया था, उनको इस अंतिम जांच परिणाम में शामिल किया गया है और उनका उपयुक्त रूप से समाधान किया गया है।
- xix. इस दस्तावेज में “****” किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xx. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 65.33 रुपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- 4. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद "तीन तत्वों अर्थात् मॉलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियन वाले नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील जिसमें से टंगस्टन और मॉलीब्डेनम का संयोजन 4 प्रतिशत – 11.5 प्रतिशत और वेनेडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत, कार्बन 0.7 प्रतिशत – 1.3 प्रतिशत के बीच और क्रोमियम 3.5 प्रतिशत – 4.6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए" है।
- 5. हाई स्पीड स्टील हाई अलॉय टूल स्टील होते हैं जो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के कार्यकारी तापमान तक लगभग 60-67 एचआरसी की अपेक्षित कार्यकारी शक्ति बनाए रखने में सक्षम होते हैं जिससे कटिंग पावर अथवा ऐज होलिंग में ह्रास के बिना बड़ी हुई मशीन क्षमता सुनिश्चित होती है। उनकी कार्यकारी विशेषताएं प्राथमिक रूप से टेम्परिंग में उन्हें रोके रखने के कारण सख्त एवं टेम्पर्ड मैट्रिक्स की रेड हार्डनेस तथा क्रोमियम मॉलीब्डेनम, वेनेडियम और टंगस्टन, कार्बन के संयोजन में, द्वारा निर्मित हाई कार्बाइड की मौजूदगी होती हैं। ये कार्बाइड टूल वियर को अत्यधिक कम करते हैं अर्थात् कटिंग ऐज पर घिसाई की दर में सुधार होता है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- 6. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
 - क. विचाराधीन उत्पाद "तीन तत्वों अर्थात् मॉलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियन वाले नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील जिसमें से टंगस्टन और मॉलीब्डेनम का संयोजन 4 प्रतिशत – 11.5 प्रतिशत और वेनेडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत, कार्बन 0.7 प्रतिशत – 1.3 प्रतिशत के बीच और क्रोमियम 3.5 प्रतिशत – 4.6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए" है। संबद्ध सामानों को हाई वर्किंग हार्डनेस, हाई वियर रेसिस्टेंस, टेम्परिंग में हाई रिटेंशन और रेड हार्डनेस तथा हाई टफनेस की विशेषता वाला माना जाता है।
 - ख. संबद्ध सामानों का प्रयोग हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। संबद्ध उत्पादों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के "लौह एवं उसकी इस्पात वस्तुएं", अध्याय शीर्ष 72 के तहत वर्गीकृत किया गया है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 72281010 और 72281090 है। तथापि, सामानों का आयात 7228 के अन्य शीर्षों के तहत भी किया जाता है। घरेलू उद्योग के अनुसार, उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित सामान भौतिक एवं

रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है।

- ग. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने अपने उत्पाद को बहुत ही स्पष्ट और तकनीकी तरीके से यहां तक कि संबद्ध सामानों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट की वास्तविक रेंज देकर परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त, इस स्पष्ट परिभाषा से उत्पाद को सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा उनकी प्रयोगशालाओं में आसानी से जांचा भी जा सकता है। इसके मद्देनजर, उत्पाद क्षेत्र का आरोप अस्पष्ट होने के नाते गलत है और तथ्यों के गलत समझने पर आधारित है।
- घ. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पीसीएन वार विश्लेषण देना चाहिए था, यह अनुरोध है कि निर्यातकों/आयातकों द्वारा व्यक्त धारणा कि कीमत विश्लेषण सही नहीं है, इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स द्वारा समर्थित नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन उन कीमतों पर आधारित है जो कि गलत और भ्रामक विचार है तथा इसे सीधे रद्द किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के सभी ग्रेडों की समग्र औसत कीमत एम2 की कीमत की तरह समान है जो भारी रूप से आयातों और घरेलू बाजार का पूर्व प्रभावी भाग बनता है। यह स्थिति होने पर सभी ग्रेडों को एक साथ लेकर उनके लिए भारित औसत निर्यात कीमत एम2 ग्रेड की कीमत के लगभग समान होगी।
- ङ. कुछ ग्रेडों को हटाने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनका कभी भी उन उत्पादों को शामिल करने का इरादा नहीं था जो न तो उनके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और न ही उनकी उत्पाद श्रृंखला के स्थानापन्न हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि लिखित अनुरोध के अगोपनीय रूपांतर में तकनीकी विशिष्टि प्रदान करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों को माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के विशिष्ट अनुदेशों के बावजूद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोध में कुछ भी नहीं दिया गया है।
- च. कॉइल और शीट रूप में हाई स्पीड स्टील को हटाने के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसे कभी भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। घरेलू उद्योग के अनुसार उन्होंने खुद ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को विशिष्ट सीमा शुल्क शीर्ष में प्रतिबंधित किया है जो कि बार और रॉडों के संबंध में ही है।
- छ. कुछ मोटाई के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वि 4 एमएम से 170 एमएम तक की मोटाई का उत्पादन कर सकते हैं। इसके मद्देनजर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, यदि 4 एमएम से कम और 170 एमएम से अधिक मोटाई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाता है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के विशेष अनुदेशों के बावजूद उन उत्पादों की कोई तकनीकी विशिष्टि लिखित में नहीं दी है जो उनके अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग की जानी चाहिए। इसके मद्देनजर, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि हाई स्पीड स्टील में अलग किए जाने के अनुरोध को रद्द किया जाए।
- झ. विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि इन तर्कों में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया पाटनरोधी कानून में कोई संगत कारक नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया है कि उत्पादन प्रक्रिया को प्राधिकारी द्वारा किसी भी पूर्व जांच में विचाराधीन उत्पाद की पहचान करते समय निर्धारित कारक कभी नहीं माना गया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि उनके द्वारा उत्पादित एचएसएस की गुणवत्ता देश में सर्वोत्तम है।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. यह कि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया है और उसे बहुत अस्पष्ट रखा है ताकि जिन उत्पादों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है, उन्हें उत्पाद क्षेत्र में शामिल किए जा सकें।
- ख. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की पूरी रेंज का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने उन कुछ उत्पादों को अलग करने की भी मांग की है जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है। उन्होंने ब्रोच और टैप्स के विनिर्माण

में प्रयुक्त उत्पादों को हटाने के लिए भी अनुरोध किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित उत्पादों को हटाने का भी अनुरोध किया है।

ग. उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उत्पाद रेंज में कीमत अंतर भी है और इसीलिए उन्होंने पीसीएन वार विश्लेषण के लिए अनुरोध किया है।

घ. यह कि आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान समान वस्तु नहीं है।

ङ. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त तथा चीन में उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया भिन्न है और इसीलिए चीन से आयातित संबद्ध सामानों को समान वस्तु नहीं माना जा सकता।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है:

"तीन तत्वों अर्थात् मॉलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियम वाले नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील जिसमें से टंगस्टन और मॉलीब्डेनम का संयोजन 4 प्रतिशत – 11.5 प्रतिशत और वेनेडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत, कार्बन 0.7 प्रतिशत – 1.3 प्रतिशत के बीच और क्रोमियम 3.5 प्रतिशत – 4.6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए।"

9. हाई स्पीड स्टील हाई अलॉय टूल स्टील होते हैं जो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के कार्यकारी तापमान तक लगभग 60-67 एचआरसी की अपेक्षित कार्यकारी शक्ति बनाए रखने में सक्षम होते हैं जिससे कटिंग पावर अथवा ऐज होलिंग में ह्रास के बिना बड़ी हुई मशीन क्षमता सुनिश्चित होती है। उनकी कार्यकारी विशेषताएं प्राथमिक रूप से टेपरिंग में उन्हें रोके रखने के कारण सख्त एवं टेम्पर्ड मैट्रिक्स की रेड हार्डनेस तथा क्रोमियम मॉलीब्डेनम, वेनेडियम और टंगस्टन, कार्बन के संयोजन में, द्वारा निर्मित हार्ड कार्बाइड की मौजूदगी होती हैं। ये कार्बाइड टूल वियर को अत्यधिक कम करते हैं अर्थात् कटिंग ऐज पर घिसाई की दर में सुधार होता है।

10. संबद्ध सामानों का प्रयोग हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। संबद्ध उत्पादों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के "लौह एवं उसकी इस्पात वस्तुएं", अध्याय शीर्ष 72 के तहत वर्गीकृत किया गया है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 72281010 और 72281090 है। तथापि, सामानों का आयात 7228 के अन्य शीर्षों के तहत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और उत्पाद क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है तथा उत्पाद विवरण विरोध की स्थिति में रहता है।

11. जहां तक पीसीएन वार विश्लेषण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक विशिष्ट पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन वार विश्लेषण एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.4 निर्यातक के घरेलू बाजारों में विद्यमान कीमतों और भारत में उसकी निर्यात कीमत की उचित एवं समुचित तुलना अधिदेशित करता है। इस मामले में यह नोट किया जाता है कि पीसीएन वार विश्लेषण के लिए अनुरोध आयातकों द्वारा किया गया है न कि निर्यातकों से, जिनकी संगत सूचना पीसीएन वार विश्लेषण के लिए अपेक्षित है। किसी भी सहयोगी निर्यातक ने इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया है और न ही इस संबंध में कोई आंकड़े दिए हैं।

12. प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि केवल कीमतों के अंतर पीसीएन वार विश्लेषण का दावा करने के लिए आधार नहीं हो सकते क्योंकि कीमत ही वह घटक है जो कि जांच का मामला है। जो भी पक्षकार पीसीएन वार विश्लेषण की मांग करता है उसे आवश्यक रूप से समुचित एवं उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद अंतर हेतु तकनीकी आधार प्रस्तावित करना चाहिए। किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसी कोई सूचना अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है, फिर भी प्राधिकारी पाते हैं कि आयातों तथा घरेलू बिक्री का बढ़ता हुआ हिस्सा केवल एक ग्रेड अर्थात् एम2 (लगभग 94 प्रतिशत) का है। सहयोगी निर्यातक भी पूर्व प्रभावी रूप से एम2 ग्रेड (लगभग 40 प्रतिशत) की ही आपूर्ति कर रहे हैं। उपर्युक्त तथ्य यह सिद्ध करता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही सहयोगी निर्यातकों ने पीसीएन वार विश्लेषण का प्रस्ताव क्यों नहीं किया है।

13. अतः उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी संबद्ध देशों के सभी सहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की भारित औसत तुलना के लिए भारित औसत लेना निश्चित करते हैं।

14. जहां तक कुछ मोटाई को अलग करने का संबंध है, प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 4 एमएम से कम और 170 एमएम से अधिक की मोटाई को अलग करने का प्रस्ताव किया था। जहां तक फ्लैट उत्पादों को अलग करने के लिए निर्यातकों के अनुरोध का संबंध है, घरेलू उद्योग ने

अपने प्रत्युत्तर विवरण में यह तर्क दिया है कि काँइलें और शीटें विचाराधीन उत्पाद का भाग कभी नहीं थीं क्योंकि उनके द्वारा उल्लिखित अध्याय शीर्ष केवल बार और रॉडों के लिए हैं। ऐसी स्थिति होने पर कोई विशिष्ट विलगन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्राधिकारी किसी भी भ्रम से बचने के लिए विचाराधीन उत्पाद का विवरण उपयुक्त रूप से स्पष्ट करना उचित मानते हैं। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में प्राप्त प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और इस जांच परिणाम में उनको हल किया गया है।

15. जहां तक उत्पादन प्रक्रिया में अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यवाहियों के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि हाई स्पीड स्टील का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से तीन प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं अर्थात् पारंपरिक इनगट कास्टिंग, इलेक्ट्रोड स्लेग रिफाइनिंग (ईएसआर) तथा पाउडर मेटालर्जी (पीएम)। पारंपरिक इनगट कास्टिंग में आधारभूत कच्ची सामग्री के कचरे और फेरो अलॉय को पिघलाने के लिए इलैक्ट्रिक आर्क फरनेस रूट (ईएएफ) का प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग उसे बोहलर ऑस्ट्रिया द्वारा अंतरित इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। इलेक्ट्रोड स्लेग रिफाइनिंग (ईएसआर) प्रक्रिया में इनगट का उत्पादन मिलाकर किया जाता है। सख्त तथा कठोर अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित बहुत ही महीन सूक्ष्म संरचना वाले इनगट का उत्पादन करने के लिए सल्फर को और कम करने के लिए उसे पुनः पिघलाया जाता है। इस प्रक्रिया में मॉल्टन ड्रॉपलेट हॉट स्लेग से कूसिबिल में गुजरते हैं और उससे परिष्कृत होते हैं। ठोसीकरण के बाद, परिष्कृत इनगट को टर्निंग, पिलिंग आदि के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। सामान्य रूप में बड़े आकारों के लिए ईएसआर को प्राथमिकता दी जाती है और पूर्व के प्रचालन को पूर्णतः नकारा जाता है। तथापि, यह एक धीमी और महंगी प्रक्रिया है जिस पर डायमीटर के बड़े आकारों के लिए प्रभाव होता है। पाउडर मेटालर्जी के मामले में, इंडक्शन भट्टी में उत्पादित द्रव धातु को बारीक चूर्ण बनाने के लिए गर्म नाइट्रोजन गैस के संपर्क में लाकर एटामाइज किया जाता है। इस पद्धति में ड्रॉपलेट की बौद्धि में मॉल्टन धातु का परिवर्तन शामिल है जो बाद में बहुत ही महीन कणों के आकार के चूर्ण में ठोस बन जाती है। इस प्रक्रिया का प्रयोग कठिन टूल और एरोस्पेस उद्योगों तथा उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अत्यधिक अंतिम अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी विनिर्माण लागत बहुत अधिक है। 4 एमएम से 170 एमएम के आकारों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों और आयातित सामानों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है। यह भी नोट किया गया था कि पूर्व प्रभावी रूप से आयात भी केवल इसी रेंज में हैं। अतः यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में अंतर संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट द्वारा यह माना गया था कि:

"यह अनुरोध कि आयातित सामानों का विनिर्माण भिन्न प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और यह कि आयातित सामान गुणवत्ता में भिन्न हैं तथा जांच परिणामों को अवैध नहीं करते। विनिर्माण की प्रक्रिया पाटनरोधी कानून के तहत संगत कारक नहीं है। गुणवत्ता अंतर भी वास्तविक नहीं है। आयातित सामानों और घरेलू रूप से उत्पादित सामानों का समान प्रयोग है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन्हें "समान वस्तु" सही माना गया है। इन तथ्यों और परिस्थितियों में इन अपीलों में किए गए अनुरोधों का कोई औचित्य नहीं है। अपीलें विफल होती हैं और रद्द की जाती हैं।"

16. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों को ध्यान में रखा है और बारों तथा रॉडों के डायामीटर की रेंज के संबंध में निम्नलिखितानुसार मानते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रेंज के निचले सिरे के लिए घरेलू उद्योग ने साक्ष्य दिए हैं जो 4 एमएम तक की निचली सीमा का औचित्य बनाते हैं। तथापि, ऊपरी स्तर के लिए न तो घरेलू उद्योग और न ही आयातकों ने 163 मि.मी. से 170 मि.मी. के बीच डायामीटर के संबद्ध सामानों का आयात किया है। साथ ही, इस बैंड में घरेलू उद्योग की कोई बिक्री नहीं है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी 4 एमएम से 163 एमएम तक के डायामीटर की एचएसएस बारों और रॉडों के डायामीटर को उत्पाद क्षेत्र से प्रतिबंधित करते हैं।
17. उपर्युक्त के मद्देनजर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है:

"तीन तत्वों अर्थात् मॉलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियन वाले 4 एमएम से 163 एमएम तक की डायामीटर के नॉन कोबाल्ट ग्रेड हाई स्पीड स्टील के बार और रॉडों, 4 प्रतिशत – 11.5 प्रतिशत के बीच टंगस्टन और मॉलीब्डेनम तथा अधिकतम 3.5 प्रतिशत वेनेडियम के संयोजन में, कार्बन की मात्रा 0.7 प्रतिशत – 1.3 प्रतिशत के बीच और क्रोमियम 3.5 प्रतिशत – 4.6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए।" शीटें, प्लेटों और काँइलों सहित किसी अन्य रूप में विचाराधीन उत्पाद को अलग किया जाता है।

18. समान वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।"

19. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयातित सामान नियमों के अनुसार समान वस्तु है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- यह याचिका संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि. (जिसे यहां बाद में याचिकाकर्ता/आवेदक भी कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध सामानों का प्रमुख उत्पादक है और इसीलिए नियमावली की परिधि में घरेलू उद्योग बनने के लिए उसका स्पष्ट आधार है।
- याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान किसी भी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध (प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) भी नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत पात्र घरेलू उद्योग है।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- आवेदक ने कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत होने वाले देश में अन्य सभी उत्पादकों के ब्यौरे नहीं दिए हैं।
- ग्रेफाइट इंडिया लि. एक एकाधिकारिक उत्पादक है क्योंकि भारत में वे ही एकमात्र उत्पादक हैं जो वाणिज्यिक मात्राओं में आपूर्ति कर रहे हैं।
- याचिकाकर्ताओं को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने यह प्रमाणित नहीं किया है कि वे पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान किसी भी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

"ख" "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

23. आवेदन पत्र घरेलू बाजार में वाणिज्यिक मात्राओं का उत्पादन करने वाले एकमात्र घरेलू उत्पादक मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि. द्वारा दायर किया गया है।

24. याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 85 प्रतिशत से अधिक है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रमाणित किया है कि वे न तो निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध हैं और न ही उन्होंने आयात किया है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि याचिकाकर्ता ने नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षा पूरी की और नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।

इ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- याचिकाकर्ता ने केवल उस सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है जिसकी गोपनीयता के लिए नियमों के तहत अनुमति दी गई है और जो प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार है।
- याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दिया है और कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सूचना का कोई विशेष उदाहरण उल्लिखित करने में सक्षम नहीं रहा है जिसका गोपनीय होने का दावा किया गया हो और जिसकी गोपनीयता नियमों के तहत औचित्यपूर्ण नहीं है।
- भारत में निर्यातों की मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्री की कुल मात्रा, उत्पादन, बिक्री, भारत को निर्यातों के लिए औसत कीमत जैसी सूचना सूचीबद्ध रूपांतर में दी गई है क्योंकि यह सूचना व्यापार स्वामित्व वाली सूचना है।
- यह कि उत्तरदाता निर्यातक, निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का सार्थक सार प्रदान न कर भारतीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि उत्तरदाता निर्यातकों ने सभी मात्रा संबंधी सूचना को गोपनीय रखा है। इसके अतिरिक्त, उत्पादकों/निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा दायर उत्तर उनके संबंधित प्रश्नावली के उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर दायर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी विशेष दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में है। याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर ध्यान न दें और निर्यातकों के उत्तरों को भी रद्द करें तथा उनकी बात पर अलग-अलग विचार न करें।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- याचिका में अत्यधिक गोपनीयता है। याचिका में मात्रा संबंधी सूचना के संबंध में भी पूर्णतः कोई सूचना नहीं दी गई है।
- घरेलू उद्योग ने अपनी लागत के पर्याप्त ब्यौरे भी नहीं दिए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अनुबंध क से ठ तक गोपनीय रखा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना"

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना

के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अनुच्छेद 6.5 कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि उसके प्रकटन से प्रतिस्पर्द्धी को काफी प्रतिशत लाभ होगा अथवा क्योंकि उसके प्रकटन से सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है), अथवा जो किसी जांच में एक पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई है, 28 में दिखाए गए अच्छे कारण पर प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार से माना जाएगा। इस प्रकार की सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 6.5.1 प्राधिकारी को गोपनीय सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उसके अगोपनीय सारांश की आवश्यकता होगी। ये सारांश विश्वास में प्रस्तुत सूचना के साथ की पर्याप्त समझ के अनुमति देने के लिए पर्याप्त व्यौरों में होगी। अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ऐसे पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि वह सूचना अति संवेदनशील नहीं है। ऐसी अपवादस्वरूप परिस्थितियों में कारणों का एक विवरण दिया जाना चाहिए कि सारांश संभव क्यों नहीं है।

अनुच्छेद 6.5.2 यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं और यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को या तो सार्वजनिक नहीं करना चाहता या सामान्यकृत रूप में अथवा सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करना चाहता है तो प्राधिकारी तब तक उस सूचना को महत्व नहीं देंगे जब तक कि वो उपयुक्त स्रोतों से उनकी संतुष्टि न हो जाए कि सूचना सही है।

अनुच्छेद 6.5.2 की पादटिप्पणी (पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार की पादटिप्पणी 18) में निम्नलिखित प्रावधान है:- सदस्य सहमत हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध स्वेच्छाचारी रूप से रद्द नहीं किए जाने चाहिए।"

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/सूचनाओं/ अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

च. विविध मुद्दे

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. यह कि उत्तरदाता प्रयोक्ता एसोसिएशनों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता। इन एसोसिएशनों को केवल तभी जांचों में हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है यदि वे प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार यह सिद्ध करें कि अधिकतर सदस्य

या तो संबद्ध सामानों के आयातक हैं या उत्पादक हैं। यह नोट करना व्यावहारिक है कि अधिकतर परीक्षण संबंधित एसोसिएशन की कुल सदस्यता के संदर्भ में लागू की जानी होती है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसा कोई अभ्यास हितबद्ध पक्षकार माने जाने के लिए आधारभूत अपेक्षाओं को सिद्ध करने हेतु एसोसिएशन द्वारा किया गया हो। चूंकि, किसी भी एसोसिएशन ने अपने संबंधित क्रियाकलापों सहित अपने सदस्यों की सूची नहीं दी है, अतः किसी भी परिस्थिति में उत्तरदाता एसोसिएशनों को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता।

- ii. यह कि उत्तरदाता पक्षकारों का यह तर्क कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग की एकाधिकार की स्थिति बनेगी, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि इस तर्क में बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी द्वारा बार-बार यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य किसी आयात को रोकना नहीं है बल्कि विशेष स्रोतों से पाटन द्वारा बनी स्थिति को हल करना है। पाटनरोधी शुल्क देश विशिष्ट शुल्क होने के नाते आयातक संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार अथवा कमी करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि आयात उचित कीमत वाले होने पर भी शुल्क लगाए जाने के बाद भी आ सकते हैं। अंतिम रूप से एकाधिकार केवल तभी रह सकता है, यदि बाजार में एक ही आपूर्तिकर्ता हो जो कि स्थिति नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यहां तक कि एक उत्पादक कोई एकाधिकार नहीं बनाता क्योंकि सामान पूरे विश्व में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से बाजार स्थल में पहुँचना जारी रहते हैं।
- iii. यह कि विलंब से संबद्ध सामानों की आपूर्ति से संबंधित अनुरोधों के संबंध में घरेलू उद्योग प्रयोक्ताओं और उनकी एसोसिएशन के ऐसे दावों को नकारता है। इसके अतिरिक्त, वे अपने दावों के समर्थन के लिए कोई साक्ष्य रिकार्ड में देने विफल रहे हैं जो भी उनके दावों की असत्यता सिद्ध करता है। वस्तुतः सस्ती कीमत वाले आयातों की मौजूदगी के कारण उपभोक्ता घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों को खरीदने से शर्मा रहे हैं। यह तथ्य भी इस तथ्य से सिद्ध है कि संबद्ध देशों से अनुचित कीमत वाले आयातों को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा रही है।
- iv. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट उसके समग्र प्रचालनों तथा कंपनी के निष्पादन का अवलोकन दर्शाती है न कि उन विशिष्ट ग्रेडों अथवा विशिष्ट उत्पादों का निष्पादन मूल्यांकन जो कि जांच के तहत हो सकते हैं। यह मुद्दा कई अन्य मामलों में विवाद की विषय-वस्तु था और यह निरंतर माना गया है कि बहु-उत्पाद कंपनियों के लिए वार्षिक रिपोर्टों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। यह दृष्टिकोण पूर्ण कानूनी परिधि पर आधारित है कि जो जांचाधीन है, वह कंपनी नहीं है बल्कि विचाराधीन उत्पाद है। घरेलू उद्योग के निष्पादन को कानून के प्रावधानों के अनुसार अकेले विचाराधीन उत्पाद के लिए जांचा जाना चाहिए।
- v. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र पूर्णतः अधिनियम और कानूनों के अनुसार है तथा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार भी है। अतः हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध प्रपत्र के अनुसार नहीं हैं, रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- vi. यह कि उत्पादकों/निर्यातकों के भारत में संबद्ध पक्षकार हैं और इसीलिए वास्तविक निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए उनके उत्तरों और लेखाओं की समुचित रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि आयातक निर्यातकों से छूट प्राप्त कर रहे हैं जिसे वे अपने ग्राहकों को दे रहे हैं।
- vii. यह कि निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा दायर आंकड़ों और सूचना की जांच उनके आंकड़ों की सत्यता की जांच करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और डीजी सिस्टम के आंकड़ों से की जानी चाहिए।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने याचिका का मूल्यांकन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटन करार के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार समुचित रूप से नहीं किया है और इसीलिए जांच को रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

- ii. यह कि घरेलू उद्योग क्षमता संबंधी कठिनाई के कारण महीनों से आदेश पूरे करने में सक्षम नहीं है। आपूर्ति में यह कठिनाई प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए विवश करती है।
- iii. किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का पूर्ण एकाधिकार बन जाएगा और इसका संबद्ध सामानों के उत्पादकों से संबंधित पारि-प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. जहां तक उत्तरदाता पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि याचिका में कमियां हैं और इसीलिए जांच को रद्द किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने याचिका निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार दायर की है। वर्तमान जांच अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क दर्शाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया के आधार पर शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने जहां भी कहीं अपेक्षित हुआ है, अतिरिक्त सूचना की भी मांग की है और उसका सत्यापन किया है।
34. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आवेदन पत्र की वैधता का मूल्यांकन करने में विफल रहे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत के समय नियम 5 के क्षेत्र में प्रथम दृष्टया आधार पर प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन करने का सीमित दायित्व ही है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अंतिम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा समुचित जांच और सत्यापन के बाद घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अतः जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में अपनाए गए मानदंड पृष्ठभूमि में पीछे रह जाते हैं और जांच का परिणाम प्रमुखता ले लेता है।
35. जहां तक नियम 2(ग) के अनुसार व्यापार एसोसिएशनों को अपात्र हितबद्ध पक्षकार मानने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि यद्यपि एसोसिएशनों द्वारा दायर उत्तरों को रद्द करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्क में औचित्य है, तथापि वे मानते हैं कि प्रयोक्ता एसोसिएशन भी महत्वपूर्ण शेरधारक हैं और इसीलिए उनके अनुरोधों पर जांच के व्यापक हित में समुचित रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
36. जहां तक घरेलू उद्योग के एकाधिकार के मुद्दे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि संबद्ध सामानों के अन्य उत्पादक भी हैं, तथापि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य किसी आयात को रोकना नहीं है बल्कि विशिष्ट स्रोतों से पाटन द्वारा सृजित स्थिति को हल करना है। पाटनरोधी शुल्क उत्पादित विशिष्ट शुल्क होने के नाते आयातक संबद्ध देशों से तथा उनकी इच्छा पर अन्य देशों से भी उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
37. प्राधिकारी ने मैसर्स जियांग्सु टियानगोंग टूल्स कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स टियानगोंग डेवलेपमेंट हांगकांग कं. लि. (निर्यातक) के संबद्ध आयातक मैसर्स टीजीके स्पेशल स्टील कं. लि. का स्थल सत्यापन किया है। प्राधिकारी ने पाया कि मैसर्स टीजीके स्पेशल स्टील कं. लि. द्वारा सूचित किए गए आंकड़े उनके वित्तीय लेखों से मेल नहीं खा रहे थे। साथ ही, मैसर्स टीजीके स्पेशल स्टील कं. लि. द्वारा सूचित की गई मात्राएं डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मेल खाती हुई नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त वे संबद्ध सामानों की बिक्री घाटे पर कर रहे हैं। अतः निर्धारित निर्यात कीमत तदनुसार समायोजित की गई है।
38. प्राधिकारी ने एक प्रयोक्ता, मैसर्स जे के फाइल्स (इंडिया) लि. के दावे की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उनके दावों का सत्यापन भी किया है। तथापि, उनके आंकड़ों में कुछ विसंगतियां पाई गई थीं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

39 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- i. याचिकाकर्ता ने जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- ii. याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा दिए गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। याचिकाकर्ताओं ने कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री

बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के लिए निर्यात कीमत समायोजित की है।

- iii. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों में पूरी तरह से कमी है और वे नवीनतम व्यापार सूचना के अनुसार दायर नहीं किए गए हैं।
- iv. चीन में उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और इसीलिए उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसार निर्मित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए "फ्रांस" को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश मानें और विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से दी गई कीमत अथवा देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करें।
- v. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे संबंधित आयातक के आंकड़ों की जांच करें।

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण संबद्ध देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए।
 - ख. सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई अवधारणाएं स्वीकार्य नहीं हैं और इस प्रकार संबद्ध देशों में वास्तविक स्थितियों के कारण वे अवधारणाएं प्रतिनिधि कारक नहीं होंगी।
 - ग. प्रयोक्ताओं ने सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय चीन के लिए फ्रांस को प्रतिनिधि संबद्ध देश का प्रयोग करने का विरोध भी किया है।

41. प्राधिकारी द्वारा जांच

9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्भूत वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

42. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं जिनमें उन्हें सलाह दी गई कि वे निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से सूचना दें। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- a. एचईवाई स्पेशल स्टील कं. लि., चीन
- b. टियानगोंग डेवलेपमेंट हांगकांग कंपनी लिमिटेड
- c. जियांग्सु टियानगोंग टूल्स कंपनी लिमिटेड

43. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन. गण. का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या:-

- i. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन. गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है;
- ii. इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- iii. इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं;
- iv. विनिमय दर का परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है।

44. प्राधिकारी यह पाते हैं कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि लिखित अनुरोध के बाद घरेलू उद्योग ने फ्रांस को चीन के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक प्रतिनिधि देश (तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था) मानने का सुझाव दिया। तथापि, निर्यातकों और प्रयोक्ता उद्योग ने अनुरोध किया कि फ्रांस को प्रतिनिधि देश नहीं माना जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा फ्रांस को एक प्रतिनिधि देश चुनने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को कोई विश्वसनीय सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि केवल विवरण पैरा 7 के तहत निर्धारित किए गए अनुसार विश्वसनीय सूचना का प्रमाण नहीं हो सकता। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई अन्य अनुरोध/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

45. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां

उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

46. उपर्युक्त के मद्देनजर, भारत में चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य उपयुक्त लाभ जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित मानक निर्मित उत्पादन लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार कर "कोई अन्य आधार" पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ब्राजील और जर्मनी से उत्पादकों और निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य

47. ब्राजील और जर्मनी से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। ब्राजील और जर्मनी में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियम 6(8) के तहत सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर अर्थात् उपयुक्त लाभ जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित मानक निर्मित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। ब्राजील और जर्मनी के लिए प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

क. मैसर्स टियानगोंग डेवलेपमेंट हांगकांग कंपनी लिमिटेड और जियांग्सु टियानगोंग टूल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में निर्यात कीमत

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर जांच की अवधि के दौरान डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार कुल लगभग 90 प्रतिशत आयात के हैं। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के नमूना निर्यात बीजकों की परस्पर जांच मात्राओं और कीमतों का सह संबंध बनाने के लिए डेस्क अध्ययन के भाग के रूप में डीजी सिस्टम के आंकड़ों के साथ भी की गई है।
49. निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर में कंपनी ने घोषित किया कि जांच की अवधि के दौरान उनके भारतीय बाजार के लिए बिक्री के दो चैनल थे अर्थात् असंबद्ध भारतीय अंतिम प्रयोक्ता को सीधे बिक्री और संबंधित व्यापारी के माध्यम से भारतीय संबद्ध आयातक को अप्रत्यक्ष बिक्री भारत को कुल निर्यात बिक्री में से *** मी. टन (10-20 प्रतिशत) असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही बिक्री की गई थी और ** मी. टन (80-90 प्रतिशत) की मात्रा संबद्ध व्यापारियों के माध्यम से संबद्ध आयातक को की गई थी। 4 एमएम से कम और 170 एमएम से अधिक डायामीटर को निर्यात कीमत परिकलन के क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि उपर्युक्त चैन में भारतीय असंबद्ध ग्राहक को *** मी. टन (10-20 प्रतिशत) का सीधे निर्यात किया है और *** मी. टन (80-90 प्रतिशत) का निर्यात संबद्ध भारतीय आयातक को संबद्ध व्यापारी के माध्यम से किया। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, समुद्री बीमा, पैकिंग लागत, ऋण लागत, पत्तन प्रभार आदि के निमित्त समायोजन का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन तथा सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में उपयुक्त सह संबंध के बाद उसे स्वीकार किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि संबद्ध आयातक को हानियां हो रही हैं, अतः उसकी हानि को भी निर्यात कीमत की गणना करते समय उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दी गई है।

ख. मैसर्स एचईवाई स्पेशल स्टील कं. लि., चीन के मामले में निर्यात कीमत

50. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में कंपनी ने घोषित किया कि जांच की अवधि के दौरान उन्होंने *** मी. टन का निर्यात सीधे ही किया जिसमें से *** मी. टन संबद्ध सामानों का भारत में असंबद्ध आयातकों को 4 एमएम से 170 एमएम डायामीटर के बीच किया गया। निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, समुद्री बीमा, वैट समायोजन, ऋण लागत, पत्तन प्रभार आदि के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और आवश्यक सत्यापन के बाद उसे स्वीकार किया गया है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ग. ब्राजील और जर्मनी से उत्पादकों और निर्यातकों के मामले में निर्यात कीमत

51. चूंकि, ब्राजील और जर्मनी से किसी भी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर नहीं है, अतः इन देशों से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है। प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार समुद्री भाड़ा, विदेशी बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और ऋण लागत के निमित्त और परिपाटी के अनुसार इन समायोजनों में पाए गए मानदंडों के अनुसार समायोजन किए हैं। तदनुसार, ब्राजील और जर्मनी के मामले में निर्धारित कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

पाटन मार्जिन

52. संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

	मात्रा	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	%	रेंज
एचईवाई	***	***	***	***	***	35-45
टीजी टूल्स	***	***	***	***	***	65-75
रेजिड्युअल	197	***	***	***	***	75-85
ब्राजील	147	***	***	***	***	40-50
जर्मनी	51	***	***	***	***	40-50

ज. मूल्यांकन तथा क्षति एवं कारणात्मक संपर्क की जांच के लिए सिद्धांत

घरेलू उद्योग के विचार

53. वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए क्षति संबंधी अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने जांच की अवधि में काफी वृद्धि के साथ इन वर्षों में वृद्धि दर्शाई है। आयातों ने भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी वृद्धि दर्शाई है।
 - मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में काफी रहा है। संबद्ध देशों ने ही घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं दिया है बल्कि बहुत कम समय में अन्य देशों का हिस्सा भी दिया है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कम हुआ है।
 - विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों में कटौती से भारतीय उत्पादक के पास उपलब्ध विकल्प केवल आयात कीमतों में परिवर्तनों के अनुरूप अपनी कीमतें रखना अथवा आदेश खोना था और इसीलिए पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान बाजार हिस्सा कम हुआ।
 - घरेलू उद्योग की कीमतें उन कीमतों का प्रभाव दर्शाती हैं जो घरेलू बाजार में निर्यातकों द्वारा दी जा रही हैं।
 - कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, सकारात्मक और काफी है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास हो रहा है क्योंकि वे उपयुक्त मात्रा में अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं।
 - घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभ के संदर्भ में तेजी से कम हुआ है। वस्तुतः घरेलू उद्योग की लाभप्रद स्थिति हानियों, निवेश पर आय में बदल गई है और नकद लाभ भी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप रहा है।
 - घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट संबद्ध देशों से गैर-लाभप्रद कीमतों पर आयात मात्रा में काफी वृद्धि के कारण थी।
 - बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि से कम थी और इस प्रकार पाटित आयात घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव बना रहे हैं।

- ix. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को, यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, निरंतर क्षति का खतरा है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

54. वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए क्षति संबंधी अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि उनका तुलन-पत्र काफी लाभ दर्शा रहा है।
 - संबद्ध देशों से आयातों का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है।
 - यह कि कोई कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास नहीं है और इसीलिए संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग का किसी क्षति का दावा रद्द किया जाना चाहिए।
 - घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आयातों के संबंध में सुधार हुआ है।
 - घरेलू मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के परिणामस्वरूप खपत में वृद्धि को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई।
 - यह कि घरेलू उद्योग ने अगोपनीय याचिका में उल्लिखित किए गए अनुसार पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति होने का दावा किया है।
 - यह कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से क्षति हो रही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

55. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती।
56. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (iv) निम्नानुसार बताता है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"

57. प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किया गया क्षति विश्लेषण वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
58. भारत में घरेलू मांग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन जैसे तत्वों पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया है।

क. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

59. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिए गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा निम्नलिखित है:

	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
ब्राजील से आयात	मी. टन	120	107	90	147
चीन से आयात	मी. टन	575	672	629	1,074
जर्मनी से आयात	मी. टन	29	27	54	51
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	725	806	773	1,272
अन्य देशों से आयात	मी. टन	152	160	257	138
कुल आयात	मी. टन	876	965	1,030	1,410
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	118	161
घरेलू बिक्री-आवेदक	मी. टन	901	876	906	1022
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	101	113
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	200	190	200	205
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	100	102.5
कुल मांग (मी. टन)	मी. टन	1,977	2,032	2,136	2,637
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	133
कुल आयात में हिस्सा					
ब्राजील से आयात	%	14%	11%	9%	10%
चीन से आयात	%	66%	70%	61%	76%
जर्मनी से आयात	%	3%	3%	5%	4%
संबद्ध देशों से आयात		83%	83%	75%	90%
अन्य देशों से आयात	%	17%	17%	25%	10%
कुल मांग में हिस्सा					
संबद्ध देशों से आयात	%	37%	40%	36%	48%
अन्य देशों से आयात	%	8%	8%	12%	5%
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	56%	52%	52%	47%

60. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के कुल आयातों और बाजार हिस्से में संबद्ध देशों का हिस्सा पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में पूर्ण दृष्टि से बढ़ा है।

ख. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करने की अपेक्षा होती है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतें कम करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो कि सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए

घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत से की गई है।

क. कीमत कटौती

62. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ आयातों की पहुँच कीमत की तुलना की है:

	मात्रा	आयात मात्रा	पहुँच मूल्य	निवल बिक्री कीमत	कीमत कटौती		
	देश	मी. टन	रु. / मी. टन	रु. / मी. टन	रु. / मी. टन	%	रेंज
2015-16	ब्राजील	120	***	***	***	***	0-10
	चीन	575	***	***	***	***	(0)-(10)
	जर्मनी	29	***	***	***	***	(20)-(30)
2016-17	ब्राजील	107	***	***	***	***	(0)-(10)
	चीन	672	***	***	***	***	0-10
	जर्मनी	27	***	***	***	***	10-20
2017-18	ब्राजील	90	***	***	***	***	0-10
	चीन	629	***	***	***	***	10-20
	जर्मनी	54	***	***	***	***	(10)-(20)
जांच की अवधि	ब्राजील	147	***	***	***	***	10-20
	चीन	1074	***	***	***	***	30-40
	जर्मनी	51	***	***	***	***	10-20

63. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य में पूरी क्षति जांच अवधि में गिरावट आई। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान सभी स्रोतों से कीमत कटौती सकारात्मक है।

ख. कीमत न्यूनीकरण और ह्रास

64. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा में कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो कि सामान्य अवधि में अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने निम्नलिखितानुसार क्षति की अवधि में लागतों अथवा कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया।

	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संबद्ध देशों के आयातों का पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	578765	488129	410080	344550
सूचकांक	सूचीबद्ध	100	84	71	60
बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	90	93
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	80	82
-----------	----------	-----	----	----	----

65. संबद्ध देशों से आयातों का पहुँच मूल्य पूरी क्षति जांच अवधि में कम हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि पहुँच मूल्य में बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक गिरावट आई।

ग. जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री (क्षति मार्जिन)

66. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की स्थिति की भी जांच की है। यह निम्नलिखितानुसार है:

देश	यूनिट	ब्राजील	चीन	जर्मनी	संबद्ध देश
पहुँच मूल्य	रु. / मी. टन	417488	344550	410171	344550
क्षति रहित कीमत	रु. / मी. टन	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रु. / मी. टन	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	30-40	60-70	30-40	55-65

67. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री का सामना करना पड़ा है।

ग. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

68. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

69. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

- i. **बाजार हिस्सा:** घरेलू उद्योग के आयातों, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से के व्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
ब्राजील से आयात	मी. टन	120	107	90	147
चीन से आयात	मी. टन	575	672	629	1,074
जर्मनी से आयात	मी. टन	29	27	54	51
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	725	806	773	1,272
अन्य देशों से आयात	मी. टन	152	160	257	138
कुल आयात	मी. टन	876	965	1,030	1,410
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	118	161
घरेलू बिक्री-आवेदक	मी. टन	901	876	906	1022
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	101	113

अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	200	190	200	205
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	100	102.5
कुल मांग (मी. टन)	मी. टन	1,977	2,032	2,136	2,637
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	133
कुल मांग में हिस्सा					
संबद्ध देशों से आयात	%	37%	40%	36%	48%
अन्य देशों से आयात	%	8%	8%	12%	5%
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	56%	52%	52%	47%

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा क्षति जांच अवधि के दौरान कम हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि कुल मांग में जर्मनी का बाजार हिस्सा केवल लगभग 2 प्रतिशत के स्तर पर रहा है और ब्राजील का बाजार हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत के स्तर पर रहा है जो कि चीन जैसा नहीं है, जिसने 29 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक काफी मात्रा में हिस्सा बढ़ाया है।

- ii. **लाभप्रदता:** घरेलू उद्योग की लाभप्रद स्थिति से जांच की अवधि और पूर्व वर्ष में हानियां हुईं। वह स्थिति निम्नलिखितानुसार है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	90	93
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	80	82
लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	32	-151	-174
ब्याज	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	110	131
पी बी आई टी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	25	-176	-86
मूल्यहास	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	28	-35	-123	355
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	-92	-26

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि और 2016-17 में हानियों के साथ क्षति की अवधि में गिरावट आई है।

- iii. **निवेश पर आय:** निवेश पर आय ने भी नीचे दर्शाए गए अनुसार लाभ की तरह समान प्रवृत्ति अपनाई है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
नियोजित पूंजी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	104	113

निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	24	-170	-76

iv. **उत्पादन एवं क्षमता उपयोग:**

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	3000	3000	3000	3000
कुल उत्पादन	मी. टन	1237	1077	1109	1273
कुल उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	1001	897	879	1030
क्षमता उपयोग	%	41%	36%	37%	42%

घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है, यद्यपि उनकी संस्थापित क्षमता पूरी मांग पूरा कर सकती है।

v. **बिक्री मात्रा और मूल्य:** निम्नलिखित तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आंशिक वृद्धि हुई है। देश में मांग में भी वृद्धि हुई है। तथापि, उनकी बिक्री मांग के अनुपात में नहीं बढ़ी है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
मांग (मी. टन)	1,977	2,032	2,136	2,661
बिक्री (मी. टन)	901	876	906	1022
बिक्री मूल्य (रु. लाख)	***	***	***	***
बिक्री कीमत (रु. /मी. टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	90	80	82

vi. **मालसूची:** संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	56	64

उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि 2016-17 तक घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट आई। तथापि, जांच की अवधि में वह पुनः बढ़ी।

vii. **रोजगार एवं मजदूरी:** यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या पूरी क्षति जांच अवधि में समान रही है। रोजगार एवं मजदूरी के संबंध में स्थिति निम्नलिखितानुसार है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
कर्मचारी	सूचीबद्ध	100	100	100	100
मजदूरी	रु.	***	***	***	***
मजदूरी	सूचीबद्ध	100	102	89	76

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
मजदूरी/कर्मचारी	रु./सं.	***	***	***	***
मजदूरी/कर्मचारी	सूचीबद्ध	100	102	89	76

- viii. **उत्पादकता:** निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रति कर्मचारी कुल उत्पादन के संदर्भ में उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच की अवधि में नकारात्मक बना रहा। तदनुसार, उत्पादकता वह कारक नहीं है जिससे क्षति हो सके।

	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
उत्पादन (मी. टन)	मी. टन	1001	897	879	1030
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
कर्मचारी	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन/कर्मचारी	मी. टन/सं.	***	***	***	***
उत्पादन/कर्मचारी	सूचीबद्ध	100	90	88	103

- ix. **पाटन की मात्रा:** विश्लेषण यह दर्शाता है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।
- x. **पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता:** इस क्षेत्र में भावी निवेश संबद्ध देशों से आयातों की मौजूदगी के कारण प्रभावित हैं। कम हुए बाजार हिस्से के साथ निवेश पर नकारात्मक लाभप्रद आय यह दर्शाती है कि क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित है।
- xi. **घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:** जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध सामानों के लिए भारत में अच्छी बढ़ती हुई मांग है। संबद्ध देशों से आयात कीमतें घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे ही प्रभावित कर रही हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण/ ह्रासमान प्रभाव था जिससे उन्हें वित्तीय हानियाँ हो रही थीं। संबद्ध देशों और जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही लग रहा है, उनको छोड़कर अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला होने का दावा नहीं किया गया है। उत्पाद का निर्माण वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा है और इसीलिए घरेलू उद्योग के सामने आई कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकता।
- xii. **वृद्धि:** आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री और उत्पाद के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी। तथापि, घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर आय जैसा वित्तीय निष्पादन नकारात्मक रहा। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि से घरेलू उद्योग में लाभ में वृद्धि आरामदायक नकद प्रवाह और निवेश पर आय में वृद्धि की उम्मीद की थी। तथापि, घरेलू उद्योग उसे हासिल करने में सक्षम नहीं था।

झ. प्रकटन पश्चात विवरण

घरेलू उद्योग से प्रकटन पश्चात विवरण

70. यह कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को या घरेलू उद्योग को उन्हें हटाने के लिए उनके मामले को सिद्ध करने हेतु विश्लेषण के लिए कोई तकनीकी आंकड़े नहीं दिए हैं। इसके अतिरिक्त, अवरोही कीमत अंतरों के आधार पर ही पीसीएन वार विश्लेषण के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष सिद्ध है कि भारित औसत विश्लेषण का प्रस्तावित सिद्धांत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संदेह से परे सबसे उपयुक्त होगा। अतः अंतिम जांच परिणाम में उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
71. यह कि चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ब्राजील और जर्मनी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है, अतः प्राधिकारी को चाहिए था कि वे क्षति मूल्यांकन करते समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/साक्ष्य को स्वीकार करते। इसके अतिरिक्त, पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/सूचना तथा घरेलू उद्योग को बाद में क्षति के संबंध में

सूचना अपरिवर्तित रहती है और इसीलिए घरेलू उद्योग विनम्रतापूर्वक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे कृपया दोनों संबद्ध देशों पर शुल्क की सिफारिश करें।

72. यह कि कम बाजार हिस्सा किसी भी देश को हटाने के लिए तब तक मानदंड नहीं हो सकता जब तक कि वे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अनुसार 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम सीमा से ऊपर हैं। यह भी अनुरोध किया जाता है कि कम बाजार हिस्सा प्राधिकारी द्वारा किसी भी मामले में कभी भी मानदंड नहीं रखा गया है, जैसा कि उपर्युक्त प्रावधान उनमें उल्लिखित शर्तों के अध्यक्षीन संचयन की अनुमति देता है। उन्होंने हाल की जांच की शुरुआत में संबद्ध देशों पर विचार किए जाने का उल्लेख भी किया है जिसमें 15 देशों में से 6 देशों में पूरी क्षति जांच अवधि में 3 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कभी पार नहीं किया।
73. यह कि ब्राजील में उत्पादकों के स्वामित्व में परिवर्तन के बाद उन्होंने भारत में अपने कमीशन एजेंटों के माध्यम से भारत में आक्रामक विपणन आरंभ किया है।

हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी टिप्पणियां

74. यह कि जर्मन उत्पादक/निर्यातक भारतीय बाजार को खतरा पैदा नहीं करते। इसके अतिरिक्त, जर्मनी संरक्षणवाद और अनुचित बाजार व्यवहार के विरुद्ध लड़ाई में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सहयोगी है।
75. यह कि हाई स्पीड स्टील के लिए भारतीय बाजार तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जर्मनी का भारतीय बाजार में आयातों और मांग में बहुत कम हिस्सा है।
76. यह कि केवल एक कंपनी ने पाटनरोधी उपायों के लिए क्यों आवेदन किया है क्योंकि अन्य कंपनियों के सामने भी समान स्थिति आ रही है।
77. यह कि प्राधिकारी को टीजी टूल्स (उत्पादक) और टीजीके स्पेशल स्टील प्रा. लि. (संबद्ध आयातक) द्वारा दायर संशोधित आंकड़ों पर विचार करना चाहिए था। उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उनके द्वारा दायर संशोधित आंकड़ों पर विचार करें।
78. एचएसएस उद्योग अन्य इस्पात क्षेत्र के उद्योगों से पूर्णतः भिन्न है। स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद कम आपूर्ति की भिन्न विशेषता वाला परंतु अत्यधिक उच्च मूल्य वाला है। एचएसएस के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री वेनेडियम की कीमत बहुत अस्थिर है। इन परिस्थितियों में टीजीके स्पेशल स्टील कं. लि. की बिक्री नीति एक व्यापारी के रूप में बाजार परिवर्तनों के साथ उसकी कीमत में उतार-चढ़ाव ला सकती है। यह स्पष्ट करता है कि आयातक को कुछ लेन-देनों में घाटों पर बिक्री करने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है।
79. यह कि घरेलू उद्योग के पास गुणवत्ता परीक्षण के लिए पर्याप्त उपस्कर नहीं हैं और वे अप्रयोज्य मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं तथा इसीलिए वे गुणवत्ता अथवा मात्रा में प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह भी एक कारण है कि उन्हें वांछित लाभ क्यों नहीं हो रहा है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि संयंत्रों की बार-बार खराबी और कमजोर रख-रखाव के कारण घरेलू उद्योग क्षमता का पूरा उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है। इसके मद्देनजर, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं तो प्रयोक्ता कंपनियों का बने रहना भारी रूप से कमजोर हो जाएगा।
80. यह कि प्रकटन विवरण के पैरा 4 में विचाराधीन उत्पाद के ब्यौरे दिए गए हैं। तकनीकी ब्रोशर के अनुसार उत्पादक केवल 40 प्रतिशत नॉन कोबाल्ट ग्रेड का उत्पादन करता है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग नॉन कोबाल्ट हाई स्पीड ग्रेडों के लगभग 18 ग्रेडों, यथा – टी2, एम30, एम33, एम34, एम36, एम50, एम52 आदि का उत्पादन नहीं कर रहा है। यदि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है तो विनिर्माता को उन उत्पादों का आयात करने के लिए अतिरिक्त धनराशि देनी होगी जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।
81. यह कि घरेलू उद्योग ने 6 एमएम से कम और 163 एमएम से अधिक मोटाई का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है और इसीलिए उसे सनसिटी शीट्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ तथा सीआर कॉइल्स मामले में माननीय हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अलग किया जाना चाहिए।
82. यह कि याचिकाकर्ता के पास कॉइल के उत्पादन के लिए घरेलू सुविधा नहीं है, अतः उसे उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्राधिकारी को डायामीटर के रूप में उत्पाद क्षेत्र में मोटाई स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि फ्लैट और शीटों के लिए मोटाई का प्रयोग किया जाता है जबकि बारों और रॉडों के लिए माप

- की यूनिट डायामीटर है। उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के परिभाषित क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तनों का भी अनुरोध किया है।
83. घरेलू उद्योग उसकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एचएसएस के नए ग्रेडों के विकास में लगा रहा है। संभव है कि घरेलू उद्योग ने इन नए ग्रेडों के विकास में काफी अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) खर्च किए होंगे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के लिए इन नए ग्रेडों का वाणिज्यिकीकरण करने और बाद में बिक्री पर लाभप्रद होने में कुछ समय लगेगा। घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आर एंड डी खर्चों के कारण भी हो सकती है। प्राधिकारी प्रकटन विवरण में इन अनुरोधों को नोट करने में विफल रहे हैं।
 84. घरेलू उद्योग के एचएसएस और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के बिक्री राजस्व आंकड़े यह दर्शाएंगे कि घरेलू उद्योग का मुख्य जोर विचाराधीन उत्पाद पर नहीं है बल्कि प्रमुख क्षेत्र पर है जो कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। विचाराधीन उत्पाद का बिक्री राजस्व कंपनी की कुल बिक्री के 6 प्रतिशत से कम है। दूसरी ओर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का बिक्री राजस्व कंपनी की कुल बिक्री के 90 प्रतिशत से अधिक है।
 85. यह कि भारत में उसके संबद्ध आयातक को घाटा इस तथ्य के कारण है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में भारत में संबद्ध सामानों के आयात के बाद गिरावट आई। उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे अंतिम जांच परिणाम में इस पहलू पर विचार करें।
 86. यह कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि उनके आर्थिक मानदंड सुधार दर्शाते हैं। यह बात भी दोहराई जाती है कि संबद्ध सामानों का कंपनी के कुल राजस्व में बहुत ही कम भाग है।
 87. यह कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को अधिक मूल्यह्रास और वित्तीय लागत, नए ग्रेडों का विकास करने में अक्षमता के कारण क्षति हो रही है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि नए ग्रेडों संबंधी आरएंडडी पर हुए खर्च की जांच की जाए।
 88. यह कि घरेलू उद्योग अपने मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में भारी लाभ कमा रहा है और इसीलिए संबद्ध सामानों के किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रचालनों से यह भी देखा जाता है कि उनका मुख्य जोर अन्य उत्पादों पर नहीं है, अन्य सामानों पर नहीं है। अतः संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 89. यह कि वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण अपूर्ण है और सभी "विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों" को रिकार्ड में नहीं लिया गया है।
 90. यह कि प्राधिकारी ने आयात आंकड़ों का समुचित रूप से विश्लेषण नहीं किया है। सही विश्लेषण यह दर्शाएगा कि ब्राजील कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम जाएगा। यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा परिकल्पित निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य भी आयातकों/प्रयोक्ताओं के आयात के आंकड़ों से मेल नहीं खाते।
 91. यह कि घरेलू उद्योग के पास मांग से अधिक क्षमता है और उनके ऐतिहासिक क्षमता उपयोग की पाटित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए क्षमता उपयोग के संबंध में जांच की जानी चाहिए।
 92. प्राधिकारी ने उत्पादन के संबंध में कोई टिप्पणियाँ नहीं की हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग का समान वस्तु का उत्पादन 2016-17 में 879 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 1030 मी. टन हो गया है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी तो उत्पादन में भी जांच की अवधि में गिरावट आई होती।
 93. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2016-17 में 37 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 42 प्रतिशत हो गया। यदि घरेलू उद्योग तथाकथित रूप से पाटित आयातों के कारण प्रभावित हो रहा था तो घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई होती। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति जांच अवधि में उन्हीं स्तरों पर रहा है। इस प्रकार, इस कारक के संबंध में कोई क्षति नहीं हो सकती।
 94. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि घरेलू उद्योग को एचएसएस क्षेत्र में हानियाँ कैसे हो रही हैं जबकि वस्तुतः उसे स्टील क्षेत्र में काफी लाभ हो रहे हैं। इस प्रकार की जांच प्राधिकारी द्वारा यह विचार करते हुए की जानी चाहिए कि संबंधित उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित राजस्व जांच की अवधि के दौरान स्टील क्षेत्र के कुल राजस्व का 94.36 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग के निवेश पर ने भी आय लाभप्रदता की तरह ही वही प्रवृत्ति अपनाई है।

95. प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं के अनुरोधों को भी रिकार्ड नहीं किया है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रकटन विवरण कानूनी रूप से संधारणीय नहीं है और इसीलिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इन अनुरोधों पर विचार करें और लाभप्रदता के निमित्त घरेलू उद्योग के निष्पादन की पुनः जांच करें।
96. केवल मालसूची में वृद्धि क्षति का संकेतक नहीं है। ब्रिजस्टोन टायर्स में माननीय सेसटेट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए केवल मालसूची पर ही विचार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि बिक्री मात्रा के अनुपात के रूप में भी विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी के आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग की मालसूची उसकी बिक्री में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बढ़ी है, अतः ऐसी कोई क्षति नहीं है जो घरेलू उद्योग को इस संबंध में हो रही हो।
97. घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या पूरी क्षति जांच अवधि में समान रही है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को इस संबंध में कोई क्षति नहीं हो रही है। यदि उसे कोई क्षति हो रही होती तो इन मानदंडों में गिरावट आई होती।
98. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ब्याज खर्चों तथा मूल्यहास में वृद्धि के कारण अगली सीमा तक गिरावट नहीं आई है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की है कि मूल्यहास लागत कैसे बढ़ सकती है जब क्षमता क्षति की अवधि में नहीं बढ़ी है।
99. मूल्यहास, ब्याज और अन्य संबंधित लागतों में वृद्धि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के अनुरूप है।
100. उत्तरदाता 400 सीरीज के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील के संबंध में रक्षोपाय जांच में अंतिम जांच परिणामों का उल्लेख करते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से माना गया है कि घरेलू उद्योग को हानियों के लिए असाधारण रूप से उच्च मूल्यहास और वित्त प्रभार उत्तरदायी थे जिसके परिणामस्वरूप कारणात्मक विश्लेषण विफल हो जाता है। प्राधिकारी प्रकटन विवरण में इन अनुरोधों को भी नोट करने में विफल रहे हैं।
101. यह कि निर्मित सामान्य मूल्य और एनआईपी की पुनः गणना किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम है और इससे अधिक क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के विवरण जारी करने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे कुल मिलाकर उनके पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं जिनको इस प्रकटन विवरण में संगत खंडों में और अब इस अंतिम जांच परिणाम में भी प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से ले लिया गया है। तथापि, स्पष्टता और स्पष्ट व्याख्या के लिए प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों पर अपनी जांच निम्नलिखित रूप में दोहराते हैं। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में प्रत्येक अनुरोध स्पष्ट करने के बजाए विभिन्न अनुरोधों का सार लिया और उनका उपयुक्त रूप से सारांश बनाया। ऐसी संभावना हो सकती है कि इसके कारण अनुरोध को अक्षरशः न लिया गया हो। तथापि, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में सभी संगत अनुरोधों को हल किया है।
103. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामानों की विभिन्न किस्मों की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री से संबंधित अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उद्योग में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के संबद्ध सामानों का उत्पादन करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू सत्यापन के दौरान उसका सत्यापन किया था और मानते हैं कि घरेलू उद्योग के पास ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करने की क्षमता है और उन्होंने उत्पादन किया। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक मात्राओं में संबद्ध सामानों का उत्पादन और बिक्री मांग तथा दिए गए आदेशों की बिक्री पर निर्भर होती है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की सीमा बनाते हुए इसको ध्यान में रखा है।
104. गुणवत्ता के मुद्दे के संबंध में, घरेलू उद्योग के आंकड़ों से यह सत्यापित है कि जांच की अवधि के दौरान गुणवत्ता मुद्दों के कारण उनका कुल बिक्री आय का केवल 0.56 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता में अंतर से जांच के क्षेत्र से अलग करने पर विचार ही हो सकता है, यदि उससे समान वस्तु का परीक्षण पास न करने वाली भिन्न वस्तु उभरे। इस मामले में आयातित संबद्ध सामान और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान "समान वस्तु" माने गए हैं।
105. जहां तक आयात आंकड़ों को अलग करने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों की जांच की गई है और डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से सत्यापित किए गए हैं तथा सही पाए गए हैं। यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के साथ निर्यातकों द्वारा दायर आंकड़ों की जांच भी की है और पाया कि इस जांच परिणाम के लिए प्रयुक्त आयात आंकड़े सही हैं।

106. प्रयोक्ता उद्योग के हित के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन केवल एक व्यापारिक क्षेत्र तैयार करना और पाटन के क्षतिकारक प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की परिकल्पना घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं की गई है। भारतीय पाटनरोधी नियमावली पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए कमतर शुल्क नियम को भी अपनाती है अर्थात् शुल्क कमतर पाटन अथवा क्षति मार्जिन तक सीमित है ताकि अन्य शेयरधारकों के हितों का भी समाधान हो जाए और संतुलित दृष्टिकोण लिया जाए।
107. जहां तक जर्मनी और ब्राजील से कम आयातों के मुद्दे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वे भारत में कुल आयातों और पाटित तथा क्षतिकारक कीमतों पर आ रहे आयातों का भी 3 प्रतिशत से अधिक हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जर्मन स्टील एसोसिएशन द्वारा दायर टिप्पणियां कि जर्मनी से लघु बाजार शेयर आयातों से सत्यापन नहीं किया जा सका अथवा पूरी तरह से जांच नहीं किया जा सका क्योंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भी नहीं लिया है। प्राधिकारी ने आवश्यक परिवर्तनों के बाद पहुँच मूल्य और निर्यात कीमत निकालने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि जर्मनी और ब्राजील से आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।
108. जहां तक घरेलू उद्योग के उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत के प्रभाव की जांच करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे की जांच घरेलू उद्योग के सत्यापन दौर के दौरान विस्तार से कर दी गई है और क्षति विश्लेषण में प्राधिकारी द्वारा इस पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, क्षति रहित कीमत का परिकलन अनुबंध-III के अनुसार किया गया है। इसके मद्देनजर, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को कोई पूर्वाग्रह न हो।
109. यह नोट किया जाता है कि स्थल सत्यापन के दौरान प्राधिकारी ने सत्यापन के सात माह पूर्व दायर किए गए आयातक प्रश्नावली के उत्तर में उनके अनुरोधों में त्रुटियां पाई थीं जिसमें परिशिष्ट-18 में लाभ निहित थे। तथापि, प्राधिकारी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह नोट किया गया कि जांच की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के साथ तुलना करने के बाद परिशिष्ट-12 से 18 गलत रूप से रिपोर्ट किए गए पाए गए थे क्योंकि *** रुपए का स्टॉक समायोजन (परिशिष्ट-17 में आरंभिक स्टॉक *** रुपए था और अंतिम स्टॉक *** रुपए था) उसे जोड़ने के बजाए लागत से घटाया गया था। इस प्रकार, परिशिष्ट-18 में *** रुपए का सूचित लाभ *** रुपए की हानि में संशोधित किया गया।
110. जहां तक मैसर्स टीजीके स्पेशल स्टील कं. लि. (आयातक) द्वारा सत्यापन के बाद दायर संशोधित सूचना पर विचार न करने के मुद्दे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सत्यापन के बाद दायर इस संशोधित सूचना में भी आयातक ने परिशिष्ट-18 में पहले सूचित किए गए अनुसार खर्चों के सभी शीर्षों के तहत संख्याओं में परिवर्तन किया। संख्याओं में यह परिवर्तन *** प्रतिशत से *** प्रतिशत के बीच अलग-अलग है।
111. जहां तक संबद्ध सामानों का मुद्दा याचिकाकर्ता उद्योग का प्रमुख क्षेत्र न होने का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग पर पाटित संबद्ध सामानों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए शुरू की गई है और आयोजित की गई है। चूंकि, समग्र कंपनी लाभ/हानि का जांच पर कोई प्रभाव नहीं है, अतः संबद्ध सामानों का मुद्दा प्रमुख क्षेत्र न होने का नाते उसका जांच के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं है।
112. जहां तक घरेलू उद्योग को क्षति न होने के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पाटन के कारण क्षति जांच अवधि के दौरान बिगड़ी है जिससे कीमत कटौती हुई है, नकद प्रवाह और निवेश पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण वित्तीय निष्पादन में काफी गिरावट दर्शाता है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

113. आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों के साथ क्षति के विभिन्न मानदंडों की जांच यह दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा में पूर्ण दृष्टि से तथा देश में कुल आयातों, घरेलू उत्पादन और कुल मांग के संबंध में वृद्धि हुई है। अन्य क्षति मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। कीमत प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण भी हुआ है। घरेलू

उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण भी हुआ है क्योंकि संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी है।

ट. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संपर्क

114. कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत हास तथा न्यूनीकरण प्रभाव के संदर्भ में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का वास्तविक क्षति, मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की मौजूदगी की जांच करने पर भारतीय पाटनरोधी नियमावली और पाटनरोधी संबंधी करार के तहत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मानदंडों की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए जांच की गई है कि तथाकथित पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

- i. संबद्ध देशों और 3 प्रतिशत से अधिक आयातों वाले देशों को छोड़कर प्रत्येक देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात एनआईपी से अधिक पहुंच मूल्य पर हैं।

(ख) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

- ii. संबंधित उत्पाद की मांग में पूरी क्षति अवधि में निरंतर वृद्धि रही है।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास

- iii. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कारक नहीं है।

(घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

- iv. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकती हो क्योंकि कच्ची सामग्री तथा संबद्ध सामान देश में मुक्त रूप से आयात योग्य है।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

- v. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। अतः क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू निष्पादन पर विचार किया गया है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

- vi. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि में सुधार होता रहा है।

115. उपर्युक्त से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटन को छोड़कर किसी कारक से क्षति होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

ठ. कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

116. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षति की अवधि में वास्तविक रूप से गिरावट आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध है:

- क. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ख. पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई।
- ग. पाटित आयातों के कारण हो रही कीमत कटौती घरेलू उद्योग को लागतों में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रही है जिससे जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आ रही है।

- घ. पाटित आयातों का कीमत न्यूनीकरण प्रभाव इस तथ्य से सिद्ध है कि घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में काफी गिरावट है।
- ङ. लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट सीधे ही पाटित आयातों का परिणाम है।
- च. घरेलू उद्योग की वृद्धि कीमत संबंधी आर्थिक एवं मात्रात्मक मानदंडों के संदर्भ में नकारात्मक हो गई है।
117. उपर्युक्त आधार पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई।

ड. क्षति की मात्रा तथा क्षति मार्जिन

118. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत निकाली गई है और क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देशों से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए उस पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीयों के साथ यही व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन का परिकलन सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए किया गया है और उसी उत्पादन पर प्रति यूनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय नहीं लगाए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और उसे अपनाया जा रहा है। इस प्रकार निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना निम्नलिखितानुसार क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है:

	मात्रा	क्षति रहित कीमत	पहुँच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	%	रेंज
चीन						
एचईवाईई	***	***	***	***	***	25-35
टीजी टूल्स	***	***	***	***	***	35-45
रेजिड्युअल	197	***	***	***	***	60-70
ब्राजील						
सभी उत्पादक/निर्यातक	147	***	***	***	***	30-40
जर्मनी						
सभी उत्पादक/निर्यातक	51	***	***	***	***	30-40

ढ. निष्कर्ष

119. उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जैसा कि इस जांच परिणाम में रिकार्ड किया गया है, की जांच करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:
- क. संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का आयात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन हुआ।

ख. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ग. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ण. भारतीय उद्योग के हित व अन्य मुद्दे

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
121. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप, इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए किसी आवश्यक धनराशि तक प्रतिबंधित किया जाए। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, साथ ही घरेलू उद्योग की गिरावट भी रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों को लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

त. सिफारिशें

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच के सभी पहलुओं के संबंध में सूचना देने/अनुरोध करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जैसा कि पूर्व के पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को काफी पाटन मार्जिन तथा वास्तविक क्षति सिद्ध की है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और परिणामस्वरूप क्षति को ऑफसेट करने के लिए अपेक्षित है।
123. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। अतः प्राधिकारी नीचे वर्णित स्वरूप एवं तरीके में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 6 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना जारी करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

क्रम सं.	शीर्ष*	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	उत्पादक	शुल्क राशि अमेरिकी डॉलर में	यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	72281010 और 72281090	तीन तत्वों अर्थात् मॉलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियम वाले 4 एमएम से 163 एमएम तक की डायामीटर के नॉन कोबाल्ट ग्रेड हाई स्पीड स्टील के बार और रॉडों, 4 प्रतिशत	चीन	एचईवाई स्पेशल स्टील कं. लि.	1902.34	मी. टन

		- 11.5 प्रतिशत के बीच टंगस्टन और मॉलीब्डेनम तथा अधिकतम 3.5 प्रतिशत वेनेडियम के संयोजन में, कार्बन की मात्रा 0.7 प्रतिशत - 1.3 प्रतिशत के बीच और क्रोमियम 3.5 प्रतिशत - 4.6 प्रतिशत के बीच होना चाहिए। **				
2	-वही	-वही	चीन	जियांग्सु टियानगोंग टूल्स कंपनी लिमिटेड	2275.64	मी. टन
3	-वही	-वही	चीन	क्रम सं. 1 और 2 को छोड़कर कोई भी अन्य उत्पादक	3263.68	मी. टन
4	-वही	-वही	ब्राजील	कोई भी	2147.22	मी. टन
5	-वही	-वही	जर्मनी	कोई भी	2259.22	मी. टन

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। उपर्युक्त विचाराधीन उत्पाद उस समय भी उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन होना चाहिए जब उसका आयात किसी अन्य एचएस कोड के तहत किया जाए।

** शीटों, प्लेटों और कॉइलों सहित किसी भी अन्य रूप में विचाराधीन उत्पाद को अलग किया जाता है।

थ. आगे की प्रक्रिया

124. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-dumping duty investigation concerning imports of High -Speed Steel of Non-Cobalt Grade from Brazil, China and Germany.

1. **F. No. 6/23/2018-DGTR.**—M/s Graphite India Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the

Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "High Speed Steel of Non Cobalt Grade having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, out of which combination of Tungsten and Molybdenum should be between 4% - 11.5% and Vanadium 3.5% maximum. Carbon should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%", (hereinafter also referred to as the subject goods or Product Under Consideration (PUC) from Brazil, China and Germany (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a Notification No.6/23/2018-DGTR dated 14th August, 2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the above Rule to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicant on behalf of the domestic industry, alleging dumping of " High Speed Steel of Non-Cobalt Grade having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, out of which combination of Tungsten and Molybdenum should be between 4% - 11.5% and Vanadium 3.5% maximum. Carbon should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%", (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from Brazil, China and Germany.
 - ii. The Authority notified the Embassy of China, Brazil and Germany in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - iii. The Authority issued a public notice dated 14.08.2018 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
 - iv. The Authority sent a copy of the initiation notification to above mentioned embassies in India, known producers/exporters from subject countries and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - v. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in subject countries, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
 - a. M/s Heye Special Steel Co., Ltd, China
 - b. M/s Jiangsu Tiangong Tools Co. Ltd
 - c. M/s Huangshi Jirui Industry Co. Ltd
 - d. M/s Villares Metals SA
 - e. M/s Deutsche Edelstahlwerke Services GmbH
 - vi. The Authority also allowed the extension of time for filing the questionnaire response till 22nd October 2018. The following producers / exporters filed a response to the Exporter's Questionnaire in the prescribed format.
 - f. Heye Special Steel Co., Ltd, China
 - g. Tiangong Development Hong Kong Company Limited
 - h. Jiangsu Tiangong Tools Company Limited
 - vii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - i. Addison & Co. Ltd
 - j. Associate Tool Manufacturer
 - k. Bharat Heavy Electricals Ltd
 - l. Chaman Steel Corporation
 - m. Chowgule Matrix Hobs Ltd
 - n. Cummins India Limited

-
- o. Drillbits International Pvt. Ltd
 - p. Emkay Tools
 - q. Esgi Tools Private Ltd.
 - r. Esskay Steels
 - s. Ferrocure International
 - t. Forbes & Company Limited
 - u. Futuristic Alloys & Metals Pvt. Ltd.
 - v. Goel Steel Company
 - w. Gun & Shell Factory
 - x. Imi Alloys Private Limited
 - y. Indo Schottle Auto Parts Pvt. Ltd
 - z. Izar
 - aa. J.k. Files & Tools
 - bb. Jaldhara Tools & Alloy Steels
 - cc. Kadimi Tool Mfg Co. Pvt. Ltd
 - dd. Kasco Special Tools Ltd
 - ee. M/S Delphi-Tvs Diesel Systems Ltd
 - ff. M/S. Lucas-Tvs Ltd.,
 - gg. Maini Precision Products(P)Ltd
 - hh. Manek Tools
 - ii. Miranda Tools
 - jj. Mitsubishi Hvy Ins Ind Prec Tlc Ltd
 - kk. Motherson Advanced Tooling Sol.Ltd.
 - ll. Om Steel Enterprises
 - mm. R K Enterprises
 - nn. Rifle Factory
 - oo. Rohit Industries Group P Ltd
 - pp. S.R.P. Tools Ltd
 - qq. Saatveeka Trading Company
 - rr. Sakshi Steel - N - Alloys
 - ss. Steelmen Enterprises
 - tt. Toolman Industries
 - uu. Trident Tools Pvt. Ltd.
 - vv. United Sales Enterprises
 - ww. Usha International Ltd.
 - xx. Zenith Birla (India) Ltd
- viii. Following importers/users/user association have filed their submissions/representations in the above matter.
- yy. TGK Special Steel Pvt. Ltd.
 - zz. Miranda Tools Pvt. Ltd.
 - aaa. J K Files (India) Ltd.
 - bbb. Addision & Co. Ltd

ccc. Birla Precision Technologies Ltd

ddd. Cutting Tools Manufacturers Association

- ix. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
- x. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xi. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st April 2017 to 31st March 2018 (12 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e. April 2014 to March 2015, April 2015 to March 2016, April 2016 to March-2017 and POI.
- xii. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xiii. Non-injurious price has been determined based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiv. Transaction wise data was called from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xv. On site verification of data filed by M/s TKG Special Steel Pvt. Ltd. and M/s J K Files (India) Ltd. was also carried out.
- xvi. The Authority held an oral hearing on 07.02.2019 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6 (6). The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were asked to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by other interested parties. The submissions made therein have been duly considered and addressed appropriately.
- xvii. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties and the Authority has recorded this Final Finding on the basis of facts available.
- xviii. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 16th July, 2019 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 23rd July, 2019. Comments filed have been appropriately considered. Any relevant submissions not addressed earlier have been included in the Final finding and appropriately addressed.
- xix. '***' in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs.65.33

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration as defined in the initiation notification for the purpose of present investigation is "High Speed Steel of Non-Cobalt Grade having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, out of which combination of Tungsten and Molybdenum should be between 4% - 11.5% and Vanadium 3.5% maximum. Carbon should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%".
5. High Speed Steels are high- alloy tool steels capable of maintaining the required working hardness of approx. 60-67 HRC up to working temperatures of almost 600 °C, thereby ensuring increased, machining capacity without deterioration in cutting power or edge holding. Their working characteristics are primarily due to their retention to tempering, the red hardness of the hardened and tempered matrix, and the presence of hard carbides formed by chromium, molybdenum, vanadium and tungsten in conjunction with carbon. These carbides greatly reduce tool wear, i.e., the rate of wear at the cutting edge is improved.

Submissions by the Domestic Industry

6. The submissions made by domestic industry are as follows:
 - a. The product under consideration is "High Speed Steel of Non-Cobalt Grade having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, out of which combination of Tungsten and Molybdenum should be between 4% - 11.5% and Vanadium 3.5% maximum. Carbon should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%". The

subject goods are characterized by the high working harness, high wear resistance, high retention to tempering and red hardness and high toughness.

- b. The subject goods are used for making High Speed Steel Cutting Tools. The subject products are classified under Chapter Heading 72 “Iron and Steel Articles thereof” of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 72281010 and 72281090. However, goods are imported under other heads of 7228 also. According to the Domestic Industry, there is no difference in the subject goods produced by them and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.
- c. It is further submitted by the Domestic Industry that they have defined its product in the most precise and technical way by even giving the exact range of inputs used in the manufacturing of the subject goods. Further, with this precise definition, product can be easily checked by the custom officer in their laboratories. In view thereof, the allegation of product scope being vague is incorrect and based on wrong appreciation of facts.
- d. In relation to the contention of some of the interested parties that the Domestic Industry should have given a PCN wise analysis, it is submitted that the apprehension expressed by exporters / importers that the price analysis is not correct, is not supported by the factual matrix of this case. It is further submitted by the Domestic Industry that the PCNs proposed by the user industry is on the basis of prices which is an incorrect and misleading proposition and needs to be rejected out rightly. It was further submitted by the Domestic Industry that the overall average price of all the grades of the product under consideration for the Domestic Industry is the same as the price of M2, which forms an overwhelmingly predominant part of the imports and the domestic market. That being the case, the weighted average export price for all the grades taken together will almost be identical to the price of M2 grade.
- e. In relation to exclusion of certain grades, it is submitted by the Domestic Industry that they had never intended to cover those products which are neither produced by them nor substitute their product range. Domestic Industry has further submitted that despite specific instructions of the Hon’ble Designated Authority to producer / exporters to provide technical specification in the non-confidential version of the written submission, nothing has been provided in the written submission by other interested parties.
- f. In relation to the exclusion of High-Speed Steel in Coil and sheet form, Domestic Industry has submitted that the same was never included in the scope of the product under consideration. According to the Domestic Industry they have themselves restricted the scope of the product under consideration to the specific custom heading, which deals with the bars and rods only.
- g. In relation to certain thickness, it is submitted by the Domestic Industry that they can produce thickness ranging from 4mm to 170mm. In view thereof, the Domestic Industry has submitted that it has no issue if, thickness below 4mm and above 170 mm is excluded from the scope of the product under consideration.
- h. It is further submitted by the Domestic Industry that none of the interested parties has provided any technical specification of the products which according to them should be excluded from the scope of the product under consideration in writing, despite specific instructions of the Designated Authority. In view thereof, the Domestic Industry has requested the Authority to reject the request of exclusions in the High-Speed Steel.
- i. In relation to the submissions of the interested parties relating to difference in the manufacturing process, the Domestic Industry submitted that such contentions are devoid of any merit since the production process is not a relevant factor in Anti-Dumping Law. Domestic Industry has further stated that the production process has never been considered as a determinative factor while identifying the PUC by the Authority in any of the earlier investigations. It was further submitted by the Domestic Industry that the quality of HSS produced by them is the best in the country.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

7. The other interested parties have made the following submissions on the product under consideration.
 - a. That the Domestic Industry has not defined its product properly and kept it very vague so that those products which are not manufactured by the Domestic Industry can be included in the product scope.
 - b. Domestic Industry is not capable of producing the entire range of the product under consideration. They have also demanded exclusion of certain products which are not produced by the Domestic Industry. They have also requested for exclusion of products used to manufacture Broaches and Taps. Some interested parties have also requested the exclusion of the products manufactured through different manufacturing process.
 - c. They have also submitted that there is price variation in the product range and therefore, they have requested for PCN-wise analysis.

- d. That the subject goods imported and produced by the Domestic Industry are not like article.

That the production process used by the Domestic Industry and producers in China is different and therefore, subject goods imported from China, cannot be treated as like article.

Examination by the Authority

8. The product under consideration in the present investigation as per the initiation notification is as follows-

"High Speed Steel of Non-Cobalt Grade having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, out of which combination of Tungsten and Molybdenum should be between 4% - 11.5% and Vanadium 3.5% maximum. Carbon should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%".

9. High Speed Steels are high- alloy tool steels capable of maintaining the required working hardness of approx. 60-67 HRC up to working temperatures of almost 600 °C, thereby ensuring increased, machining capacity without deterioration in cutting power or edge holding. Their working characteristics are primarily due to their retention to tempering, the red hardness of the hardened and tempered matrix, and the presence of hard carbides formed by chromium, molybdenum, vanadium and tungsten in conjunction with carbon. These carbides greatly reduce tool wear, i.e., the rate of wear at the cutting edge is improved.
10. The subject goods are used for making High Speed Steel Cutting Tools. The subject products are classified under Chapter Heading 72 "Iron and Steel Articles thereof" of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 72281010 and 72281090. However, goods are imported under other heads of 7228 also. The custom classification is however indicative only and is in no way binding upon the product scope and the product description prevails in situation of conflict.
11. As regards PCN-wise analysis, the Authority notes that PCN-wise analysis is an important element for computation of exporter specific dumping margin as Article 2.4 of Anti-Dumping Agreement that mandates a fair and proper comparison of the prices prevailing in the domestic markets of the exporter and its export price to India. In this case, it is noted that the request for PCN-wise analysis has been made by importers and not from the exporters whose relevant information is required for such a PCN-wise analysis. None of the cooperating exporters have made any such request or provided data in this regard.
12. The Authority further observes that mere differences of price cannot be a basis for claiming PCN-wise analysis, as it is the price itself which is the matter of investigation. Any party who seeks PCN-wise must necessarily propose a technical basis for the product differentiation to ensure proper and fair comparison. No such information or evidence has been placed by any party. Nevertheless, the Authority observes that the overwhelming share of imports as well as domestic sales are of only one grade. i.e., M2 (about 94%). The cooperating exporters are also predominantly supplying M2 grade only (about 95%). The aforesaid validates as to why neither the Domestic Industry nor the cooperating exporters have proposed a PCN-wise analysis.
13. Therefore, in view of the aforesaid the Authority concludes to undertake weighted average to weighted average comparison of the Normal value and Export price for all cooperating exporters from the subject countries.
14. As regards the exclusion of certain thicknesses, the Authority on the basis of the data on record and as verified, had proposed to exclude thickness below 4mm and above 170mm from the scope of the product under consideration. As regards the request of the exporters to exclude the flat products, the Domestic Industry has contended in their rejoinder statement that coils and sheets were never a part of the Product under Consideration as the Chapter Headings referred to by them are for bars and rods only. That being the case, there is no need to make any specific exclusion. However, the Authority considers it appropriate to clarify the Product under Consideration description appropriately to avoid any confusion. Accordingly, the post disclosure comments received on scope of product under consideration have been appropriately considered and addressed in this final finding.
15. As regards the difference in the production process, the Authority notes that during the proceedings, it was noticed that there are three main technologies available to produce High Speed Steel namely, Conventional Ingot Casting, Electrode Slag refining (ESR) and Powder Metallurgy (PM). In Conventional Ingot Casting the electric arc furnace route (EAF) is used for melting the basic raw materials Scrap and Ferro alloys. Domestic Industry is using this technology transferred to it by Bohler, Austria. In Electro Slag Refining (ESR) process, ingots are produced by melting, are remelted for further reduction of sulphur, phosphorous and other impurities to produce ingots having very fine microstructure required for tough and stringent applications. In this process the molten droplets pass through the hot slag into the crucible and thereby get refined. After solidification, the refined ingot is processed for turning, peeling etc. In general, ESR is preferred for large sizes and the forging operation is completely avoided. However, it is a slow and costly process, which has impact for large sizes of diameters. In the case of Powder Metallurgy, the liquid metal produced in an induction furnace is atomized by bringing it into contact with hot nitrogen gas to form minute powders. This method involves change of molten metal into a spray of droplets that later solidify into powder form of very minute particle size. This process is used for high end applications in the cutting tool, and aerospace industries and in advanced research laboratories as its manufacturing cost is very high. For the

sizes 4mm to 170 mm, the goods produced by the Domestic Industry and imported goods are used interchangeably. It was further noted that predominantly, imports are also in this range only. Therefore, it is noted that difference in production process is not relevant for defining the scope of the product under consideration. Further, in the matter of Automotive Tyre Manufacturers Association V. DA, it was held by the Hon'ble CESTAT that:

"The submissions that imported goods are manufactured through a different process and that the imported goods differ in quality also do not invalidate the findings. Process of manufacture is not a relevant factor under anti-dumping law. Quality difference is also not material. The imported goods and domestically produced goods have the same use and have been correctly held to be 'like article' by the Designated Authority. In these facts and circumstances the submissions made in these appeals have no merit. The appeals fail and are rejected."

16. The Authority has taken note of post disclosure comments on the scope of the Product Under Consideration by other interested parties and holds as under with regard to range of diameter of the bars and rods. The Authority notes that for the lower end of the range, the domestic industry has provided evidence which justifies the lower limit to 4mm. However, for the higher end, neither the Domestic Industry nor the importers have imported the subject goods of diameter between 164mm to 170mm. Also, in this band, there are no sales of domestic industry. In view thereof, the Authority restricts the product scope to diameters of Bars and Rods of HSS from diameter 4mm to 163 mm.

17. In view of the above, the product under consideration is confirmed as follows:

"Bars and Rods of Non-Cobalt Grade High Speed Steel of diameter from 4mm to 163 mm having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, with combination of Tungsten and Molybdenum between 4% - 11.5% and maximum 3.5% of Vanadium. The Carbon content should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%". The product under consideration in any other form including sheets, plates and coils are excluded.

18. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

19. After considering the information on record, the Authority holds that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions by the Domestic Industry

20. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. The petition has been filed by M/s Graphite India Limited (hereinafter also referred to as Petitioner/Applicant) for imposition of anti-dumping duty on the subject goods from subject countries. The petitioner is the major producer of the subject goods in India and therefore has clear standing to constitute domestic industry within the ambit of the Rules.
- ii. Petitioner has not imported the subject goods from any of the subject countries during the POI. Petitioner is also not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject countries. Thus, the petitioner is eligible domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

21. The submissions made by the interested parties on the standing of the Domestic Industry are as follows:

- b. Applicant has not provided details of all the other producers in the country accounting for 2% of the total production.
Graphite India Limited is a monopolistic producer, as they are the only producer in India supplying commercial quantities.
- c. Petitioners cannot be treated as eligible Domestic Industry as they have not certified that they are not related to any exporter or importer during the entire injury investigation period.

Examination by the Authority

22. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) ‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

23. The application has been filed by M/s Graphite India Ltd., the only domestic producer producing commercial quantities in the domestic market.
24. The production of the petitioner constitutes for more than 85% of the total Indian production. The petitioner has also certified that they are neither related to exporters or importers nor they have imported. Accordingly, the Authority holds that that the petitioner satisfied the requirement of standing under Rule 5(3) and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

D. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

Submissions by the Domestic Industry

25. The submissions made by domestic industry are as follows:
 - i. The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
 - ii. The petitioner has provided sufficient non-confidential version of the application and that none of the interested parties has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.
 - iii. Information such as volume of exports to India, gross volume of sales in domestic market, production, sales, average price for exports to India have been provided in indexed version as the information is business proprietary information.
 - iv. That the responding exporters have failed to fulfill their obligations under the Indian law by not providing the meaningful summary of the response to exporters' questionnaire. Domestic Industry has further submitted that responding exporters have kept all the volume related information confidential. Further, the responses filed by producers/exporters and importers are in violation of the specific guidelines issued by the Designated Authority with regard to the procedure to be followed for filing of non-confidential version of their respective questionnaire responses. Petitioner have also requested the Designated Authority to disregard the submissions of the interested parties and also to reject the response of exporters and deny them the individual treatment.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

26. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
 - i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to volume related information also.
 - ii. Domestic Industry has also not provided sufficient details of their costing. Further, they have kept Annexures A to L as confidential.

Examination by the Authority

27. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
28. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows:

“Confidential information”

- (1) *Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*”

29. The WTO Agreement on Anti-Dumping provides as follows with regard to confidentiality of information-

“Article-6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

Article-6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

Article-6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.

Footnote to Article 6.5.2 (footnote 18 of the WTO Agreement on Anti-Dumping) provides as follows— Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.”

30. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences / information's / submissions submitted by various interested parties in the form of public file.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

Submissions by the Domestic Industry

31. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. That the responding user associations cannot be considered as interested parties in terms of Rule 2(c) of the anti-dumping Rules. These associations can be permitted to participate as an interested party in the investigations only and only if it proves to the satisfaction of the Authority that the majority of the members are either importers or producers of subject goods. It is pertinent to note that the majority test is to be applied in the context of total membership of respective association. It is important to note that there is no evidence on record that such an exercise has been carried out by association to prove the basic requirements for being considered as an interested party. Since none of the association has even provided the list of their members along with their respective activities, under no circumstances, responding association can be considered as an interested party.
- ii. That the contention of responding parties that imposition of anti-dumping duties will lead to a situation of monopoly of the Domestic Industry, Domestic Industry submitted that this argument is completely devoid of any merit. It has been held by the Authority time and again that the objective of anti-dumping duties is not to block any imports but only to address the situation created by dumping from specific sources. Anti-dumping duties being country specific duties, the importers are free to import the subject goods at fair prices from the subject countries as well as from other countries. Therefore, there is no question of monopoly by Domestic Industry or causing shortage as the imports can still come after the imposition of duties given that they are fairly priced. Last but not the least, a monopoly can exist only if there is a single supplier in the market which is not the case. It is also submitted that even a single producer does not create any monopoly as the goods continue to reach the market place from other suppliers around the world.
- iii. That the submissions regarding delayed supply of subject goods, Domestic Industry denies such claim of the users and their association. Further, they have failed to place on record any evidence to support their claims which also proves the falsehood in their claims. In fact, due to the presence of cheap priced imports, the consumers are shying away from buying the domestically produced products. This fact is also evident from the fact that the unfairly priced imports from subject countries are being preferred over the goods produced by the Domestic Industry.
- iv. That the fact that Domestic Industry is a multi-product company and its Annual Report reflects its overall operations and overview of company's performance and not a performance appraisal of specific grades or specific products which may be under investigation. This issue was subject matter of dispute in several other cases and it has been

consistently held that no reliance can be placed on annual reports for multi-product companies. This approach is based on the sound legal premise that what is under investigation is not the company but the product under consideration. The performance of the Domestic Industry must be judged for the product under consideration alone in terms of the provisions of law.

- v. That the application filed by Domestic Industry is fully in accordance to the act and rules and also as per the prescribed format. Therefore, the submissions of the interested parties that application is not as per format needs to be rejected.
- vi. That the producers / exporters have related party in India and therefore, their responses and accounts need to be checked properly to find the actual export price. Domestic Industry has also submitted that importers are receiving discounts from exporters, which they are passing to their customers.
- vii. That the data and information filed by the exporters and importers needs to be checked from the DGCI&S data and DG System data to check the correctness of their data.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

32. The submissions made by the other interested parties are as follows:

- i. That the application filed by the Domestic Industry is not in the form and manner prescribed by the Authority. Further, the Authority has not evaluated the petition properly in terms of Article 5.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement read with Rule 5(3) of the AD Rules and therefore, the investigation needs to be terminated.
- ii. That the Domestic Industry is not able to fulfil orders for months, due to capacity constraints. This constraint in supply compels the users to import the subject goods.
- iii. Any imposition of duties will give the Domestic Industry complete monopoly and will have adverse impact on the ecosystem concerning producers of subject goods.

Examination by the Authority

- 33. As regards the argument of the responding parties that the petition is deficient and therefore the investigation needs to be terminated, the Authority notes that the Domestic Industry has filed petition as per the prescribed formats. The present investigation was initiated on the basis of *prima facie* evidence furnished by the Domestic Industry showing dumping, injury and causal link in accordance with the Act and Rules. The Authority has also called for additional information wherever required and verified the same.
- 34. As regards the arguments of the interested parties that the Authority failed to properly evaluate the validity of the application by the Domestic Industry in terms of the Rule 5(3) of the AD Rules, the Authority notes that the scope of Rule 5 at the time of initiation of an investigation has only a limited obligation to evaluate key parameters on *prima facie* basis. The Authority further notes that the final determination is required to be based on the information made available by the Domestic Industry as well as other interested parties after proper examination and verification by the Authority. Therefore, the parameters adopted as *prima facie* evidence used for the purpose of initiation recede in the background and the outcome of investigation assumes primacy.
- 35. As regards the issue of treating trade associations as ineligible interested parties in terms of Rule 2 (c), the Authority notes that even though there is merit in the contention of the Domestic Industry to reject the responses filed by associations, it however, holds that user associations are also important stakeholders and therefore, their submissions need to be appropriately considered in larger interest of the investigation.
- 36. As regards the issue of monopoly of the Domestic Industry, it is noted that while there are other producers of the subject goods as well, the objective of levying anti-dumping duties is not to block any imports but only to address the situation created by dumping from specific sources. Anti-dumping duties being producer specific duties, the importers are free to import the subject goods at fair prices from the subject countries and as well as from other countries of their choice.
- 37. The Authority has undertaken onsite verification of M/s TGK Special Steel Co. Ltd., related importer of M/s Jiangsu Tiangong Tools Company Limited (producer) and M/s Tiangong Development Hong Kong Company Limited (exporter). The Authority found that the data reported by M/s TGK Special Steel Co. Ltd. was not matching with their financial accounts. Also, quantities reported by M/s TGK Special Steel Co. Ltd. were found not to be matching with the DG System data. Further, they are selling the subject goods at losses. Therefore, the export price determined has been adjusted accordingly.
- 38. The Authority has also verified one of the users namely M/s JK Files (India) Ltd. to ascertain the veracity of their claim. However, certain discrepancies were found in their data.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**Normal Value****39. Submissions by the Domestic Industry**

- i. Petitioner has determined normal value in the subject countries on the basis of best information available for the purpose of the initiation.
- ii. Petitioner has relied upon import data provided by DGCI&S for determining export price. Petitioners have adjusted export price for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at ex-factory export price.
- iii. Questionnaire response filed by producers/exporters are grossly deficient and not filed in terms of the latest trade notice.
- iv. The producers in China have not claimed MET and therefore, their normal value needs to be constructed in terms of Annexure I of the AD Rule. They have further requested that the Authority to treat "France" as the appropriate market economy third country for construction of the normal value or construct the normal value on the basis of the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted.
- v. Domestic Industry also requested the Authority to scrutinize the data of related importer.

40. Submissions by the Other Interested Parties

- i. The following submissions have been made by other interested parties:
 - a. Determination of normal value and dumping margin should be based on the information provided by the exporters/producers from subject countries.
 - b. Assumptions made by the Petitioners regarding normal value are not acceptable as such assumption would not be representative due to factual conditions in the subject countries.
 - c. Users also contested the use of France as surrogate subject country for China while calculating normal value.

41. Examination by the Authority

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to the article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

42. The Authority sent questionnaires to the known exporters from subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Following producers / exporters have filed the prescribed questionnaire responses.
 - a. Heye Special Steel Co., Ltd, China
 - b. Tiangong Development Hong Kong Company Limited
 - c. Jiangsu Tiangong Tools Company Limited
43. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The exporter/ producer of the subject goods from China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-

paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:

- i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - ii. The production cost and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate
44. The Authority observes that none of the producers / exporters have claimed market economy treatment. The Authority determined the normal value in terms of Para 7 of Annexure I. It is further noted that in post written submission the Domestic Industry suggested consideration of France as a surrogate country (third country market economy) for determination of China's normal value. However, the exporters and user industry submitted that France cannot be considered as surrogate country, as no reliable information has been provided by the Domestic Industry to interested parties on selection of France as a surrogate country. They further submitted that mere statement does not tantamount to reliable information as prescribed under Para 7. No other submissions / suggestions were received from any of the interested parties.
45. Para 7 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules provides as under:
- “In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”
46. In view of the above, the normal value for the subject products imported from China PR into India is determined on "any other basis" by considering the best available information with regard to normated constructed cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits. Accordingly, the normal value determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value in case of producers and exporters from Brazil and Germany

47. No producer/exporter from Brazil and Germany has filed the exporters questionnaire response. Therefore, the Normal Value for all producers/exporters in Brazil and Germany is determined on the basis of best available information under rule 6 (8) i.e., on the basis of normated constructed cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits. The normal value so determined by the Authority for Brazil and Germany is mentioned in the dumping margin table below.

a. Export price in case of M/s Tiangong Development Hong Kong Company Limited and Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

48. The Authority notes that the response filed by cooperative producers/exporters almost accounts for 90% of total imports as per DGCIS data during POI. Further sample export invoices of cooperative producers/exporters have been cross checked with the DG-system data as part of the desk study to correlate quantities and prices.
49. In the exporters questionnaire response, the Company declared that during the POI they had two channels of sales for Indian market viz; direct sales to unrelated Indian end user and indirect sales to Indian related importer through related trader. Out of the total export sales to India, ***MT (10-20 %) was sold directly to unrelated customers and *** MT (80-90%) of the quantity to related importer through related trader. Diameter below 4mm and above 170mm

were excluded from the scope of the export price calculation. It is also noted that the above chain has exported ***MT (10-20%) direct to Indian unrelated customer and ***MT (80-90%) to related Indian importer through related trader. The exporter has claimed adjustment on account of inland freight, overseas freight, marine insurance, packing cost, credit cost, port charges etc. and the same have been accepted after necessary verification and appropriate correlation amongst cooperating producers/exporters. It is also noted that since the related importer is incurring losses, its loss is also appropriately adjusted while computing the export price. Accordingly, the export price determined is provided below in the dumping margin Table below.

b. Export price in case of M/s Heye Special Steel Co., Ltd, China

50. In the exporters questionnaire response, the Company declared that during the POI they directly exported *** MT, of which *** MT of the subject goods to India to unrelated importers were between 4mm to 170 mm diameter. The exporter has claimed adjustment on account of inland freight, overseas freight, marine insurance, VAT adjustment, credit cost, port charges etc. and the same have been accepted after necessary verification. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table below.

c. Export price in the case of producers and exporters from Brazil and Germany

51. Since there is no response from any producer/exporter from Brazil and Germany, the export prices for all the producers/exporters from these countries have been determined on the basis of information available on record. The Authority has made adjustments on account of ocean freight, overseas insurance, port expenses, inland freight, bank charges and credit cost as claimed by the petitioner and in accordance with norms observed on such adjustments as per practice in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level in case of Brazil and Germany determined is as mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Dumping Margin

DUMPING MARGIN

52. The dumping margin for the subject goods is evaluated as under:

	Qty	Normal value	Export price	Dumping margin	Dumping margin	Dumping margin
	MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%	Range
Heye	***	***	***	***	***	35-45
TG Tools	***	***	***	***	***	65-75
Residual	197	***	***	***	***	75-85
Brazil	147	***	***	***	***	40-50
Germany	51	***	***	***	***	40-50

G. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the Domestic Industry

53. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- Imports of the product under consideration from subject countries have shown increase over the years with a significant increase in POI. Imports have also shown increase in relation to production and consumption in India;
 - Market share of subject countries in demand has become significant in POI. Subject countries have not only taken the share of Domestic Industry but also of other countries in a short span of time. Market share of the domestic industry has decreased in the POI as compared to the base year.;
 - With reduction in the prices by the foreign producers, the only choice available to the Indian producer is to either realign their prices with the changes in the import prices or to lose orders and hence the market share reduced during the entire injury investigation period;
 - Domestic industry prices reflect the effect of the prices that are being offered by the exporters in the domestic market;
 - The price underselling, price undercutting is positive and substantial. Further, the Domestic Industry is suffering

from price depression as they are not able to increase its prices to reasonable terms.

- vi. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, infact the profitable situation of the Domestic Industry has turned into losses, return on investments and cash profits also followed the same trend.
- vii. The decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the import volume at non-remunerative prices from subject countries.
- viii. The increase in selling price was lower than the increase in cost of production and thus the dumped imports are creating price suppression effect on the domestic industry.
- ix. The domestic industry has suffered material injury in connection with dumping of subject goods from the subject countries. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue.

Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties

54. The following are the injury related submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority.
- i. The Domestic Industry is not suffering any injury, as their balance sheet is showing significant profits.
 - ii. The imports from subject countries have no negative impact on the performance of the Domestic Industry.
 - iii. That there is no price undercutting, price underselling, price suppression and depression and therefore, the claim of the Domestic Industry of any injury on account of imports from subject countries should be rejected.
 - iv. The profitability of the domestic industry has improved with respect to imports and vice-versa.
 - v. The inability of the domestic industry to meet the domestic demand has resulted in the increase in imports to fulfil the rise in consumption.
 - vi. That the Domestic Industry has claimed to be materially injured due to the dumped imports as stated in the non-confidential Petition.
 - vii. That the Domestic Industry is suffering injury on account of factors other than imports from subject countries.

Examination by the Authority

55. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

56. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry. Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

57. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority.
58. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II of the Rules supra.

A. Volume Effect of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

59. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries is as under:

Particulars	Units	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Imports from Brazil	MT	120	107	90	147
Imports from China	MT	575	672	629	1,074
Imports from Germany	MT	29	27	54	51
Imports from Subject Countries	MT	725	806	773	1,272
Imports from other countries	MT	152	160	257	138
Total Imports	MT	876	965	1,030	1,410
Trend	Indexed	100	110	118	161
Domestic Sales-Applicant	MT	901	876	906	1022
Trend	Indexed	100	97	101	113
Other Producers Sales	MT	200	190	200	205
Trend	Indexed	100	95	100	102.5
Total Demand (MT)	MT	1,977	2,032	2,136	2,637
Trend	Indexed	100	103	108	133
Share in Total Imports					
Imports from Brazil	%	14%	11%	9%	10%
Imports from China	%	66%	70%	61%	76%
Imports from Germany	%	3%	3%	5%	4%
Imports from Subject Countries		83%	83%	75%	90%
Imports from Other Countries	%	17%	17%	25%	10%
Share in Total Demand					
Imports from Subject Countries	%	37%	40%	36%	48%
Imports from Other Countries	%	8%	8%	12%	5%
Sale of Domestic Industry	%	56%	52%	52%	47%

60. It is noted from the above table that share of subject countries in total imports and market share of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms in POI as compared to the previous years.

B. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

61. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries have been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from subject countries.

a. Price Undercutting

62. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry as below:

Year	Quantity	Import Quantity	Landed Value	Net Selling Price	Price Undercutting		
	Country	MT	Rs. / MT	Rs./ MT	Rs./ MT	%	Range
2015-16	Brazil	120	***	***	***	***	0-10
	China	575	***	***	***	***	(0)-(-10)
	Germany	29	***	***	***	***	(20)-(-30)
2016-17	Brazil	107	***	***	***	***	(0)-(-10)

Year	Quantity	Import Quantity	Landed Value	Net Selling Price	Price Undercutting		
2017-18	China	672	***	***	***	***	0-10
	Germany	27	***	***	***	***	10-20
	Brazil	90	***	***	***	***	0-10
	China	629	***	***	***	***	10-20
	Germany	54	***	***	***	***	(10)-(20)
POI	Brazil	147	***	***	***	***	10-20
	China	1074	***	***	***	***	30-40
	Germany	51	***	***	***	***	10-20

63. It is noted that the landed value from subject countries declined throughout the injury investigation period. It is further noted that price undercutting is positive from all sources during the period of investigation.

b. Price Suppression and Depression

64. In order to determine whether the imports from the subject countries are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed Value of Imports of Subject Countries	Rs./MT	578765	488129	410080	344550
Index	Indexed	100	84	71	60
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	90	93
Domestic Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	80	82

65. The landed value of imports from the subject countries decreased throughout the injury investigation period. It is further noted that the landed value declined more than the decline in cost of sales and selling price.

c. Price Underselling (injury margin) during POI

66. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of imports from subject countries. The same is as below:

Particulars	Unit	Brazil	China	Germany	Subject Countries
Landed Value	Rs. / MT	417488	344550	410171	344550
NIP	Rs. / MT	***	***	***	***
Price Underselling	Rs. / MT	***	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***	***
Price Underselling	Range	30-40	60-70	30-40	55-65

67. It is noted from the above table that the domestic industry has suffered price underselling on account of imports of the subject goods from the subject countries.

C. Economic Parameters of the Domestic Industry

68. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry,

including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

69. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

i. **Market share:** The details of imports, domestic sales and the market share of the domestic industry is as below:

Particulars	Units	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Imports from Brazil	MT	120	107	90	147
Imports from China	MT	575	672	629	1,074
Imports from Germany	MT	29	27	54	51
Imports from Subject Countries	MT	725	806	773	1,272
Imports from other countries	MT	152	160	257	138
Total Imports	MT	876	965	1,030	1,410
Trend	Indexed	100	110	118	161
Domestic Sales-Applicant	MT	901	876	906	1022
Trend	Indexed	100	97	101	113
Other Producers Sales	MT	200	190	200	205
Trend	Indexed	100	95	100	102.5
Total Demand (MT)	MT	1,977	2,032	2,136	2,637
Trend	Indexed	100	103	108	133
Share in Total Demand					
Imports from Subject Countries	%	37%	40%	36%	48%
Imports from Other Countries	%	8%	8%	12%	5%
Sale of Domestic Industry	%	56%	52%	52%	47%

As mentioned earlier, imports of the subject goods from the subject countries have increased in the POI as compared to the previous years. The market share of domestic sales has decreased during the injury investigation period. It is also noted that the market share of Germany in total demand has remained only at a level of about 2% and that of Brazil at a level of about 5% unlike China which has significantly increased from a level of 29% to 41%.

ii. **Profitability:** The profitable situation of the Domestic Industry resulted into losses in the POI and preceding year. The same is as follow:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	90	93
Domestic Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	80	82
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	32	-151	-174
Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	110	131
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	25	-176	-86
Depreciation	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	28	-35	-123	355
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	34	-92	-26

The profitability of domestic industry has declined over the injury period with losses in POI, and 2016-17.

iii. **Return on Investment:** The return on investment has followed the same trend as of profit as depicted below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	104	113
ROI	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	24	-170	-76

iv. **Production and Capacity Utilization:**

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	MT	3000	3000	3000	3000
Total Production	MT	1237	1077	1109	1273
Total Production - PUC	MT	1001	897	879	1030
Capacity Utilization	%	41%	36%	37%	42%

The capacity utilisation of domestic industry has remained low though their installed capacity can meet entire demand.

- v. **Sales Volume and Value:** It is noted from the Table below, that the sales volume of the Domestic Industry has marginally increased in the POI as compared to the base year. The demand in the country has also increased. However, their sales have not increased in the proportion of the demand. It is also noted that the sales price of the Domestic Industry has decreased in the POI.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Demand	MT	1,977	2,032	2,136	2,661
Sales	MT	901	876	906	1022
Sales value	Rs. Lacs	***	***	***	***
Selling price	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	80	82

- vi. **Inventories:** The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	56	64

From the above, it is noted that till 2016-17 the inventory of the Domestic Industry declined. However, in the period of investigation the same has again increased.

- vii. **Employment and Wages:** It is noted that the number of the employees remained same throughout the injury investigation period. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Employees	Number	***	***	***	***
Employees	Indexed	100	100	100	100
Wages	Rs.	***	***	***	***
Wages	Indexed	100	102	89	76
Wages/employee	Rs/No.	***	***	***	***
Wages/employee	Indexed	100	102	89	76

- viii. **Productivity:** It can be seen from the table below that productivity in terms of total production per employee has increased in the POI as compared to the base year. Despite increase in productivity, the performance of the Domestic Industry continued to be negative in POI. Accordingly, productivity is not a factor that can be attributed to injury.

	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Production (MT)	Indexed	1001	897	879	1030
Employees	No.	***	***	***	***
Employees	Indexed	100	100	100	100
Production/employee	MT/No.	***	***	***	***
Production/employee	Indexed	100	90	88	103

- ix. **Magnitude of Dumping:** The analysis shows that the dumping margin determined for cooperating producers/exporter is above *de minimis* and significant.
- x. **Ability to raise Capital Investment:** The future investment in the sector is affected by the presence of imports from the subject countries. The negative profitability return on investment along with reduced market share indicates that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector is seriously affected.
- xi. **Factors affecting domestic prices:** The examination indicates that there is a healthy growing demand in India for the subject goods. The import prices from the subject countries are directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. It is also noted that the landed value of subject goods from the subject countries are below non-injurious price of the domestic industry. Further, landed value from subject countries had suppressed / depressed effect on the prices of the Domestic Industry causing financial losses to them. The imports of the product under consideration from countries other than subject countries and countries already attracting anti-dumping duty are not claimed to be injuring the domestic industry. Demand for the product is showing an increase trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the domestic industry.
- xii. **Growth:** There was positive growth of the domestic industry in terms of sales and production in the POI as compared to the base year. However, financial performance of the Domestic Industry like profits, ROI remained negative. The domestic industry has contended that with increase in demand, the domestic industry had expected growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same.

H. Post Disclosure comments

Post Disclosure comments from the Domestic Industry

70. That none of the interested parties has provided any technical data for analysis either to the Authority or to the Domestic Industry to prove their case for exclusion. Moreover, merely based on random price differences no request of PCNs-wise analysis can be entertained. It is therefore, clear that the conclusion of the Authority regarding the proposed methodology of weighted average analysis being most appropriate in the facts and circumstances of the case is established beyond any doubt. Therefore, the same should be confirmed in the final findings.
71. That since none of the interested parties provided any information in relation to Brazil and Germany, the Authority ought to have accepted the information / evidence submitted by the Domestic Industry while carrying out the injury assessment. Further, the information / evidence submitted by the Domestic Industry in relation to dumping and subsequent injury to Domestic Industry remained uncontroverted and therefore, the Domestic Industry humbly requests the Authority to kindly recommend duty on both the subject countries.
72. That the low market share cannot be a criterion for exclusion of any country so long they are above the statutory *de minimis* limit of 3% in terms of para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules. It is further submitted that low market share has never been a criterion in any of the cases by the Authority as the aforesaid provision allows for cumulation subject to the conditions mentioned therein. They have also cited consideration of subject countries in recent initiation wherein 6 countries out of 15 countries never crossed share of 3% in the entire injury investigation period.
73. That the post change in the ownership of producers in Brazil, they have started aggressive marketing in India, through their commission agents in India.

Post Disclosure comments from the interested parties

74. That the German producers / exporters do not pose a threat to the Indian market. Moreover, Germany is an important and reliable ally for India in the fight against protectionism and unfair market behavior.
75. That the Indian market for High Speed Steel is of comparatively low importance. They have further submitted that Germany has very low share in Imports and demand in the Indian market.
76. That why only one company has applied for anti-dumping measures, as other companies are also facing the same situation.
77. That the Authority should have considered the revised data filed by TG Tools (producer) and TGK Special Steel Pvt. Ltd (related importer). They have requested the Authority to consider the revised data filed by them for determining injury margin and dumping margin.
78. The HSS industry is quite different from other steel segment industries. Apparently, the PUC is with a distinct character of low supply but extremely high value. The price of the raw material Vanadium used in the manufacture of HSS is very volatile. Under such circumstances, the sales policy of TGK Special Steel Co. Ltd. as a trader, may have to fluctuate its price along with market changes. This explains why the importer is being forced to sell at losses in certain transactions.
79. That the Domestic Industry does not have adequate equipment for quality testing and are using obsolete machinery and therefore, they cannot fully meet the requirement of the users either in quality or in quantity. It is further submitted that this is also one of the reasons why they are not making desired profits. It is further submitted that due to frequent break down and poor maintenance of the plant, the Domestic Industry has not been able to fully utilize the capacity. In view thereof, if anti-dumping duties are imposed, the survival of user companies will be severely weakened.
80. That the para 4 of the disclosure provides the details of the product under consideration. As per the technical brochure, the producer only produces 40% of non-cobalt grades. It is further submitted that Domestic Industry is not producing around 18 grades of Non-Cobalt High-Speed grades such as T2, M30, M33, M34, M36, M50, M52, etc. In case anti-dumping duties are recommended, the manufacturer will have to pay additional amount to import the products, which are not manufactured by the Domestic Industry.
81. That the Domestic Industry has not produced and supplied thickness below 6 mm and above 163 mm and therefore, the same should be excluded in terms of decision of Hon'ble Haryana and Punjab High Court in the case of Suncity Sheets Pvt. Ltd. vs Union of India and CR Coils case.
82. That the petitioner does not have the in-house facility for producing coil. Therefore, it should be excluded from the product scope. They further requested that the Authority should clarify 'thickness' as 'diameters' in the product scope, as thickness is used as a unit of measurement for flat & sheets while for the bars & rods the unit of measurement is diameter. They further requested necessary changes in the defined scope of the product under consideration.
83. The domestic industry has engaged in the development of new grades of HSS as per its own Annual Report. It is possible that the domestic industry would have incurred significant Research and Development (R&D) expenses in the development of these new grades. Further, it would take some time for the domestic industry to commercialize and subsequently become profitable on selling of these new grades. The decline in the domestic industry's profits, cash profits and ROCE is also to be attributed to the R&D expenses. The Authority has failed to take note of these submissions in the Disclosure Statement.
84. The domestic industry's sales revenue figures of HSS and Graphite Electrodes would show that the main focus of the domestic industry is not on PUC but on the major segment which is Graphite Electrodes. Sales revenue of the PUC constitutes less than 6% of the total sales of the company. On the other hand, sales revenue of graphite electrodes constitutes more than 90% of the total sales of the company.
85. That the losses to its related importer in India is due to the fact that the prices of raw material declined post importation of the subject goods in India. They have requested the Authority to consider this aspect in the final findings.
86. That the Domestic Industry has not suffered any injury due to imports from subject countries, as their economic parameters shows improvement. It is further reiterated that the subject goods accounts for very insignificant portion of the total revenue of the company.

87. That there is no causal link between the injury suffered by the Domestic Industry and imports from subject countries. They have further submitted that Domestic Industry is suffering because of high depreciation and finance cost, inability to develop new grades. They have also requested to examine the expenses incurred on R&D of new grades.
88. That the Domestic Industry is making huge profit in their main business segment and therefore, no protection is required for subject goods. It is also seen from their operations that their main focus is on other products and not on the subject goods. Therefore, there is no requirement for recommending anti-dumping duties on the subject goods.
89. That the disclosure statement issued by the Authority in the current investigation is incomplete, and all the “essential facts under consideration” have not been put on record.
90. That the Authority has not analyzed the import data properly. The correct analysis would show that Brazil would go below 3% of the total imports. It is further submitted that the export price and landed value calculated by the Authority also does not match with the import’s figures of importers / users.
91. That the Domestic Industry has excess capacity compared to demand and their historical capacity utilization needs to be examined in order to analyze impact of dumped imports on capacity utilization.
92. The Authority has not made any observations regarding production. It is submitted that the domestic industry’s production of the like article has increased to 1030 MT during the POI from 879 MT in 2016-17. If the domestic industry was suffering injury, the production would have declined in the POI.
93. The domestic industry’s capacity utilization has increased from 37% in 2016-17 to 42% in the POI. If the domestic industry was being impacted due to allegedly dumped imports, the domestic industry’s capacity utilization would have instead declined. Further, the domestic industry’s capacity utilization has been at such levels throughout the injury investigation period. Thus, no injury can be attributed with regard to this factor.
94. The Authority has not examined how the domestic industry has been making losses in the HSS segment when in fact it has been making significant profits in the steel segment. Such an examination should be made by the Authority considering that the revenue earned by the domestic industry for the product concerned is 94.36% of the total revenue of the steel segment during the POI. The domestic industry’s returns on investment have followed the same trend as that of profitability.
95. The authority has even not recorded the Respondents’ submissions. This is a violation of principles of natural justice. The Disclosure Statement is not legally sustainable and the Authority is therefore urged to consider these submissions and re-examine the domestic industry’s performance on account of profitability.
96. Mere increase in inventory is not an indicator of injury. Keeping in mind the decision of the Hon’ble CESTAT in *Bridgestone Tyres*, inventory must not be examined in isolation but as a proportion of sales volume. As per the Authority’s data, the domestic industry’s inventories have increased keeping in mind the increase in its sales. Therefore, there is no injury that the domestic industry is suffering in this regard.
97. The number of employees engaged by the domestic industry has remained the same throughout the injury investigation period. The productivity per employee has increased in the POI. This indicates that the domestic industry is not suffering any injury in this regard. If it were suffering any injury, these parameters would have declined.
98. The domestic industry’s cost of sales has not declined to a further extent due to increase in interest expenses and depreciation. The Authority has not examined how depreciation costs could have increased when capacity has not increased in the injury period.
99. The increase in depreciation, interest and other related costs is commensurate with the decline in the profitability of the Domestic Industry.
100. The Respondents cite the final findings in the safeguards investigation on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 Series which categorically held that abnormally high depreciation and finance charges were responsible for the losses to the domestic industry as a result of which the causation analysis fails. The Authority has even failed to take note of these submissions in the Disclosure Statement.

101. That the constructed normal value and NIP needs to be recomputed as the capacity utilization of the Domestic Industry is less and this will lead to higher injury margin and dumping margin.

Examination by the Authority

102. The Authority notes that all the issues raised by the other interested parties post issue of disclosure statement are by and large reiteration of their earlier submissions which have been appropriately dealt by the Authority in the relevant sections in the disclosure statement and now in the final findings also. However, for the sake of clarity and explicit narration, the Authority reiterates its examination below on the post disclosure submissions made by the other interested parties. The authority had in the disclosure statement, captured essence and summarized various submissions appropriately rather than narrating each and every submission. It may be likely that on account of this, a submission might have not been narrated verbatim. However, the Authority has addressed all relevant submissions in this final findings.
103. With regard to the submission of capability, production and domestic sales of different types of the subject goods by the domestic industry, the Authority notes that in the disclosure statement it has been clarified that the domestic industry has the capability to produce different types of subject goods as per the requirement of the customers. Further, the Authority during the domestic verification had verified the same and holds that the domestic industry has the capability to produce and did produce the subject goods as per requirements of the customers. Further, production and sales of subject goods in commercial quantities is dependent on demand and sales orders placed. The Authority has taken this into account while limiting the scope of the product under consideration.
104. With regard to the issue of quality, it is verified from the data of Domestic Industry that they have merely 0.56% of total sales return due to quality issues during POI. Further, difference in quality could only lead to consideration of exclusion from scope of investigation if it leads to emergence of a different article not passing the test of a like article. In this case the imported subject goods and the goods produced by the domestic industry have been held as 'like article'.
105. As regards the issue of import data segregation, the Authority notes that the import data submitted by the Domestic Industry is examined and verified from DGCI&S import data and found to be in order. It is further submitted that the Authority has also examined the data filed by exporters with the DGCI&S import data and found that the import data used for this finding is in order.
106. As regards the issue of interest of user industry, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is only to create a level playing field and to provide relief to domestic industry due to injurious effect of dumping. Further, it is noted that the anti-dumping duty is not envisaged to provide undue protection to the domestic industry. The Indian AD Rules further adopt the lesser duty rule for levy of Anti-dumping duty i.e., the duty is limited to lower of the Dumping or Injury margin so that the interest of other stakeholders also gets addressed and a balanced view is taken.
107. As regards the issue of low imports from Germany and Brazil, it is noted that the same is above 3% of the total imports in India and also coming at dumped and injurious prices. The Authority further notes that the comments filed by German Steel association that with the small market share imports from Germany could not be verified or cross checked, as none of the producers / exporters have participated in the investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S import data to work out landed value and export price, after making necessary changes. The Authority therefore, holds that anti-dumping duty is warranted on imports from Germany and Brazil also.
108. As regards the request of interested parties to examine the impact of high depreciation and interest cost of the Domestic Industry, the Authority notes that this issue has been examined in detail during domestic industry's verification visit and has been appropriately taken care of by the Authority in injury analysis. Further, non-injurious price has been computed in terms of the Annexure III. In view thereof, it is noted that the Authority has taken care that no prejudice is caused to any interested party.
109. It is noted that during onsite verification, the Authority had found errors in their submissions in the IQR filed before 7 months of verification which contained profits in Appendix-18. However, it is noted by the Authority during the course of verification that, after comparing with the financial statements for the POI, the appendices 12 to 18 were found to be reported incorrectly, as the stock adjustment of Rs. *** (opening stock in appendix-17 was Rs. *** and the closing stock was Rs. ***) was deducted from the cost instead of adding the same. Thus, the reported profit of Rs. *** in Appendix-18, corrected to a loss of Rs. ***.

110. As regard the issue of not considering revised information filed post verification by M/s TKG Special Steel Co. Ltd. (importers), it is noted that even in such revised submission filed post-verification, the importer has changed the numbers under all heads of expenses as reported earlier in Appendix 18. Such change in numbers vary between ***% to ***%.
111. As regards the contention of the interested parties on the share of revenue for the HSS segment, the Authority holds that the profitability has been evaluated for the product under consideration which is only a part of HSS category. Since overall company profit / loss has no implication on the investigation and therefore, the issue of subject goods not being major segment has no influence on the outcome of the investigation.
112. As regards the issue of injury not being suffered by the Domestic Industry, the Authority holds that the financial situation of the domestic industry deteriorated during the injury investigation period on account of dumping leading to price undercutting, adversely impacting the cash flow and ROI. The analysis of economic parameters indicates significant decline in financial performance causing material injury to the domestic industry.

I. Conclusion on Material Injury

113. An examination of the various parameters of injury along with the volume and price effects of imports reveals that material injury has been caused to the Domestic Industry during the period of investigation. There is an increase in the volume of imports of subject goods from the subject countries during the injury investigation period in absolute terms as well as in relation to the total imports, domestic production and total demand in the country. Other injury parameters also indicate that the domestic industry has suffered injury on account of dumped imports of subject goods from the subject countries. With regard to price effect, it is noted that imports of the subject goods from the subject countries is undercutting the prices of the domestic industry. Further, the domestic industry has suffered price depression. The domestic industry has also suffered price suppression on account of imports of product under consideration from subject countries as sales price of subject goods has not increased in line with increase in cost of production of subject goods during the injury period.

J. Other Known Factors & Causal Link

114. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Anti-Dumping Rules and Agreement on Anti-dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the alleged dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

(a) Volume and prices of imports from third countries

- i. Imports of the product under consideration from each country other than the subject countries and countries above 3% of the imports are at landed values above the NIP.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

- ii. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period.

(c) Developments in technology:

- iii. Technology for production of the product concerned has not undergone any significant change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the Domestic Industry.

(d) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

- iv. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

(e) Export performance of the domestic industry

- v. The Domestic Industry has not exported the subject goods. Therefore, only domestic performance has been considered for injury analysis.

(f) Productivity of the Domestic Industry

- vi. It is noted that the productivity of the domestic industry has been improving over the injury investigation period.
115. From the aforesaid, the Authority concludes that there is no evidence of injury being caused due to factors other than dumping.

K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

116. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated over the injury period. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- Imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the volume of imports has increased during the injury investigation period.
 - Market share of the dumped imports increased and consequently, market share of the domestic industry declined;
 - Price undercutting being caused by the dumped imports is preventing the domestic industry from increasing its prices commensurate with the increase in costs resulting in decline in the profitability of the domestic industry during the POI.
 - The price depression effect of the dumped imports is evidenced from the fact that there is significant decline in profitability to the domestic industry;
 - Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of dumped imports;
 - The growth of the domestic industry became negative in terms of a price related economic as well as volume parameters.
117. The above grounds clearly establish existence of causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry. Thus, the Authority concludes that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

L. Magnitude of Injury and Injury Margin

118. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows;

Particulars	Qty.	NIP	Landed Value	Injury margin	Injury margin	Injury margin
	MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%	Range
China						
Heye	***	***	***	***	***	25-35
TG Tools	***	***	***	***	***	35-45

Residual	197	***	***	***	***	60-70
Brazil		***	***	***	***	
All producers/exporters	147	***	***	***	***	30-40
Germany		***	***	***	***	
All producers/exporters	51	***	***	***	***	30-40

M. Conclusions

119. After examining issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from subject countries below its normal value, thus resulting in dumping of the product.
 - The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
 - The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES.

120. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
121. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would also prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

O. RECOMMENDATIONS

122. The Authority notes that the investigation was initiated and all interested parties were given adequate opportunity to provide information/submissions on all aspect of the investigations. As stated in the foregoing paras the Authority has established significant dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports. The Authority holds that imposition of AD duty is required to offset dumping and consequential injury.
123. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder. Accordingly, antidumping duty equal to the amount mentioned in Col 6 of the table below is recommended to be imposed on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries for a period of five years from the date of issue of notification.

S. No	Heading*	Description of goods	Country of origin	Producer	Duty Amount in USD	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	72281010 and 72281090	<i>Bars and rods of Non-Cobalt Grade High Speed Steel of diameter from 4mm to 163mm having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, with combination of Tungsten and Molybdenum between 4% - 11.5% and maximum 3.5% of Vanadium. The Carbon content should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6% ",**</i>	China	Heye Special Steel Co. Ltd.	1902.34	MT
2	-do	-do	China	Jiangsu Tiangong Tools Company Limited	2275.64	MT
3	-do	-do	China	Any other producer other than serial number 1 and 2	3263.68	MT
4	-do	-do	Brazil	Any	2147.22	MT
5	-do	-do	Germany	Any	2259.22	MT

*Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.
The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code

** The product under consideration in any other form including sheets, plates and coils are excluded

P. FURTHER PROCEDURE

-
124. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR , Addl. Secy. & Designated Authority